पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.geocities.com/samaymaya/july09.pdf

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार

B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 3 अंक 40 इंदौर, सोमवार 24 अगस्त से 30 अगस्त 2009 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 लोकतंत्र लोककल्याण नहीं नींच लूट तंत्र

3 सभी मिलावटियों, सरकारी स्वा.वि., नपा, निगमों के निरीक्षक

4 प्रकृति, वनैले शूकरों की भांति उजाड़ने की दावा हंस होने का

5 छठे वेतन मान के निर्धारण में चल रही वसूली

6 १५ अगस्त जश्ने जम्हूरियत या आजादी

7 इंदौर कांड की पुनरावृत्ति देवास में भी

६२ वर्ष की आजादी के बाद भी....

राष्ट्रगीत गुलामी का, शिगूफा आजादी का

हमारे 120 करोड़ लोगों के विश्व की जनसंख्या के मान से विश्व में दूसरे स्थान पर हमारे राष्ट्र की आजादी को 62वर्ष हो चुके हो हम 1947 से 2009 में 63वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे है। पर इतने विशाल राष्ट्र का कैसा दुर्भाग्य है कि हम 62वर्ष के बाद भी 62वर्ष पूर्व के हमारे आका अंग्रेजों की महिमा मंडन कर अपनी गुलामी के गीत गा रहे हैं। देखें राष्ट्रगीत की पंक्तियां जन (के) गण, मन(से) अधिनायक जय है जिनके हम अधीन थे जो हमारे नायक थे, अर्थात अंग्रेज, भारत भाग्य विधाता, आजादी के पूर्व हमारे भाग्य के विधाता थे।

उस भारत में न केवल रहने वाले जन जो पंजाब, जिसके दो हिस्से हो गए, सिंध जो अब पूरा पाकिस्तान में है, गुजरात, मराठा अर्थात महाराष्ट्र प्रांत, द्रविड़ अर्थात दक्षिण, उत्कल अर्थात उड़ीसा, बंग अर्थात बंगाल जिसके दो हिस्से हो चुके थे पश्चिमी बंगाल भारत में है जहां वर्तमान में श्रमिकों की हितैषी लाल झंडे की सरकार है। पूर्वी बंगाल का अब अलग राष्ट्र बांगला देश बन चुका है। विंध्य की पहाड़ियां जहां मध्यप्रदेश बसा है। हिमाचल से लेकर भारत के गुजरात से लेकर दक्षिण और पश्चिमी बंगाल के किनारों से लगे समुद्र की जल तरंगे तक येसबी प्राकृतिक रचना भी उस भाग्य विधाता अंग्रेजों की जय करता है।

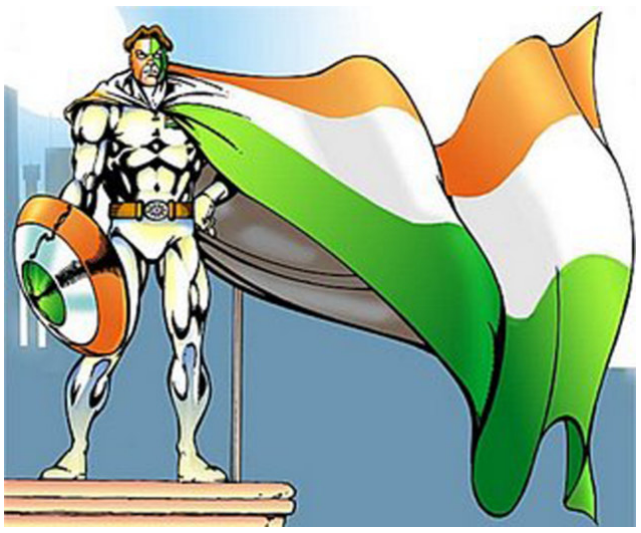

जन के गण, मन से अधिनायक की जय करते हैं जो भारत भाग्य विधाता हैं

धन्य हो इस ऐतिहासिक विशाल राष्ट्र के 20 करोड़ गुलामों जो 62 वर्ष की आजादी के बाद भी आजादी की ढोंग करते हो, अपने स्वतंत्र राष्ट्र मानकर अपनी सर्वभौमिकता अपना संविधान के अनुसार अपनी सत्ता पालने की बात करते हो, जबकि स्वयं अपने राष्ट्रगीत में अपनी गुलामी का गीत गाकर गोरों की जयकार करते हो।

वर्तमान पीढ़ी को यह नहीं मालूम होगा कि इसके रचियता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जार्ज पंचम की आगवानी में 1919 में यह **शेष पेज 2 पर**

दहशत के व्यापारी हैं कांग्रेसी

कुकर्मों को दबाने के लिए दहशत

महंगाई,दबाने स्वाइन फ्लू का राग अलापा

पूरे देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंचने और जनता को पुन राशन की दुकानों की लाईन में खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने अपना पुराना दहशत का व्यापार शुरू कर दिया है। कभी दहशत, आतंकवादी हमलों से कभी आतंकवाद का भय दिखाकर कभी स्वाइन फ्लू की दहशत फैला कर लोगों का ध्यान परिवर्तन कर ये हरामखोर कांग्रेसी गिद्ध जनता को नोंच कर अपने कुकर्मों को सफल बनाते हैं।

स्वाइन फ्लू अमेरिका की अपनी दवाओं को किसानों को बेचने का नया शिगुफा है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से मिले अनुदान से दहशत का घी खरीदकर होम करता है, उस यज्ञ के फलस्वरूप अमेरिकी कंपनियों की दवाएं वेक्सीन खड़े-खड़े पूरी दुनिया में बिक जाती है। स्वाइन फ्लू बीमारी का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया। पर हो तब तो बताएं ये स्वीज। फ्लू का अमेरिकी दवा कंपनियों की मंदी दूर कर रहा है। भारत का प्र.मं.स. मनमोहन उसकी आका सोनिया देश की जनता की सुरक्षा के नाम पर रुपए 20-25 अरब की दवाएं खरीदकर पूरे देश में भिजवाने की नौटंकी कर 2-5 अरब स्वयं डकार ले गए। अगर 15 दिन में पूरे देश में 15 मौतें हो भी गई तो 120 करोड़ के लिए कौन सा बड़ा काम हो गया। जबकि इस देश में हर दो मिनट में 3 मौतें टीबी से अर्थात 2160 मौतें हर दिन होती है। 6300 मौतें हर दिन हृदयगति रुकने से, 62000 मौतें मधुमेह से, 2740 मौतें धुमपान और तम्बाकू से, 1500 मौते प्रतिदिन कैंसर से, मलेरिया से औसतन 300 से ज्यादा मौतें प्रतिदिन हो जाती है। मौसमी बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी औसतन 400 प्रतिदिन हो जाती है। **शेष पेज 2 पर**

सीबीआई जांच चाहिए केजी ६ बेसिन धूर्त अंबानी के पास कैसे पहुंचा?

खोदे, खोजे ओएनजीसी ने गैस बेचेंगे अम्बानी

समय माया वर्षों से लिख रहा, पेट्रोलियम मंत्रालय की जालसाजी

भारत की केंद्रीय और राज्य की सत्ताएं अंबानी, टाटा, बिरला, भारती, बड़े-बड़े भूमाफिया, सफेदपोश, डकैत कैसे हांकते है। वर्तमान में चल रहे अनिल और मुकेश अम्बानी के कृष्णा गोदावरी बेसिन के ब्लाक-6 में निकाली जाने वाली गैस के राष्ट्रीय स्तर पर मचे विवाद से समझा जा सकता है। इसकी मूल जड़ में जहां अरबों रुपए का भ्रष्टाचार पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल व प्राकृतिक गैस आएंगे, के बीच हुआ है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। **शेष पेज 4 पर**

पर्यावरण, धन, मानव स्वास्थ्य सबकी बर्बादी का कारण

विश्व का चीन, अमेरिका से बड़ा, सबका शत्रु

पूरे विश्व में पूरे विश्व की मानव जाति के साथ पर्यावरण की बर्बादी, शत्रुता, दूसरों को बर्बाद करने की नीच मानसिकता का अमेरिका से बड़ा नाम चीन का है।

चीन ने पूरे विश्व के बाजारों में घातक रसायनों, धातुओं, प्लास्टिक से बने बच्चों के खिलौनों से बाजार पाटने से लेकर नकली स्तरहीन दवाइयां, बिजली का सामान स्तरहीन शीघ्र खराब हो जाने वाले कम्प्यूटरों से उनके सीडी, डीवीडी प्लेयर्स, टीवी, मोबाइल व अन्य हजारों प्रकार के उपकरणों, कपड़ों से रेडिमेड गार्मेंट्स जो घातक कृत्रिम रसायनों से बनाए गए हैं से लेकर चीनी, रेशम, स्टेपल, फाइवर, नकली घातक धातुओं से बने जेवरात और आभूषणों, आटोमोबाइल्स में कारों, मोटर सायकलों, नकली बैट्रियों, उनके स्पेयर पार्ट्स, कृषि फसलों, फलों, रसों, चाकलेट, टाफियों,साबुन, तेल से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों जो मानव त्वचा का **शेष पेज 2 पर**

श्रीलंकाई ड्रेस में नरसंहार किया भारतीय सेना ने

मनमोहन और सोनिया पर मानवाधिकार उल्लंघन का मुकदमा चलाया जाए

श्रीलंका में भीषण नरसंहार अप्रैल-मई ०९

भारत के पड़ोसी श्रीलंका में फरवरी 09 से लेकर मई-जून 09 तक लिट्टे के खात्मे की आड़ में 2 लाख से ज्यादा निरीह नागरिकों की हत्या और 50 हजार से ज्यादा लिट्टे सैनियों के सफाए में भारतीय सेना ने ही श्रीलंकाई ड्रेस पनकर यह नरसंहार किया समयमाया कांग्रेस की इन बत्तमीजियों और भीषण नरसंहार के ऊपर लगातार भारतीय और विश्व की जनता को सच्चाई परोसता आ रहा है। बेशक आत्यधिक लघ इकाई, साधनों और धन के अभाव में बिलंब होता जा रहा है। इसके विपरीत उपलब्ध साधनों से ही जनहित में

भारतीय मीडिया के बिकाऊ मानसिकता, शासन और धन की कठपुतली बन नाचने, जनता को भ्रमित करने के षड्यंत्रों में भी अकेले दम पर सच जनता को प्रस्तुत करते रहे हैं। भारतीय मीडिया ने जो परोसा वह शुद्ध बकवास थी। **शेष पेज 4 पर**

साप्ताहिक
समय माया

संपादकीय

६२ वर्ष की आजादी

लोकतंत्र लोककल्याण नहीं नींच लूट तंत्र

हमारे राष्ट्र की आजादी को 62 वर्ष हो गए 63वां स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। 62वर्ष की यात्रा में हमारा लोकतंत्र परिपक्व होने की अपेक्षा हमारे जन ने जो नेता चुनकर सत्ता सौंपी वो सत्ता में बैठते ही मानव से दानव बनकर जनकल्याण के नाम स्वकल्याण हेतु जनता को प्रताड़ित करने दहशत देकर उन्हें डरा कर उनकी मेहनत का निवाला छीनने और तिल-तिल कर रक्त पिपासु दानवबन गए।

62वर्षों में न्याय प्रणाली प्रशासन, पत्रकारिता जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है धन भौतिकवाद की मानसिकता से सत्यता, सामाजिकता, नैतिकता सबका न केवल घोर पतन हुआ और हो रहा है वरन सत्यता, न्याय, सामाजिकता, नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य राष्ट्र की प्राचीन वेदों, ऋषियों, मुनियों की सांस्कृतिक विरासत केवळ पुस्तकों के पन्नों पर धूल खाने को बाध्य हो गई। लोकतंत्र में जनतंत्र द्वारा चुने गए भ्रष्ट न केवल दानव बन जनता का रक्त पीकर ही संतुष्ट नहीं हो रहे, वरन धन के लिए विदेशी कंपनियों, सरकारों की कठपुतली बन नाचते हुए कृषि जैसे आधारभूत उद्योग जो लाखों वर्षों से मानव जीवन का आधार रही है के मूल बीजों, गेहूं , चावल, दालें, सब्जियों, फलों, मसालों, जड़ी कपास बूटियों, औषधियों, दलहनों के साथ ही तिलहनों के बिजों की मूल प्रजातियों का नष्ट करने में भी ये कृषि मंत्री दानव शरदपंवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपनी अच्छी गुणवत्ता के श्रेष्ठ श्रेणी के बीजों को विश्व के मांसेंटों जैसी अमेरिकी बीज कंपनियों को सौंप कर उनके जीएम और बीटी बीजों का राष्ट्र की कृषि भूमि का अंग बनाकर लाखों किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। इसके उरांत भी इन रक्त पिपासु दानवों, मनमोहन, सोनिया, शरद पंवार जैसों की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। पहले राष्ट्र के श्रेष्ठ उत्पादन को विदेशों को निर्यात कर मोटा कमीशन डकारो कमी होने पर वहां का सड़ा माल मोटे कमीशन पर देश में मंगवाने में फिर अनुदान का ढोंग कर जनता को राशन की लाइनों में खड़ा करने का षड्यंत्र रच फिर उनका रक्त पियो। अब केंद्र व राज्य सरकारें जनता से सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने जो राष्ट्र की समृद्धि का आधार है, रोड टेक्स, ईंधन पर कीमत 3 चौथाई टेक्स वसूलती है जनता को नोंचने के सड़कों पर टोल के माध्यम से हर 50-60 किमी पर नोंच रही है। खाद्य वस्तुओं पर बिक्री कर वसूलने के बाद भी अपनी नोंच के लिए निर्यात और समाप्ति पर आयात कर कमीशन डकार कर नोंच रही है। अब लोकतंत्र का नोंचलूट, भ्रष्टाचार से कमाई का तंत्र बन चुका है जहां जनता को नोंचने कदम पर सरकारी डकैतों का कानूनी कब्जा है।

प्रधान मंत्री, मंत्री नेता जो इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों की कठपुतली बन नाचते हैं। वो अरबों रुपए देश के संसाधनों से नोंचकर जनता को रक्त के आंसू रुलाकर विदेशी बैंकों में जमा करते रहते हैं। ये चुने तंत्र के नेता उन्हें बचाने और स्वयं को बचाने की कानूनी नौटंकियां करते रहते हैं।

कदम-कदम पर जहां भी जिस क्षेत्र में दृष्टिपात करो तो मालूम पड़ता है कि लोक प्रशासन और शासन चलाने वाला तंत्र इस भ्रष्ट और निकम्मा हो चुका है कि उसका जनता से करों में वसूलने गए वेतन और सुविधाओं से पेट भरने की तो दूर गले नहीं उतर रहा है इसलिए वो जन के कल्याण के नाम स्वकल्याण के लिए बहुमुखी अपनी नोंचखसोट के लिए योजनाएं बनाकर जनता को सब्जबाग दिखाकर ढिंढोरा पीटता हुआ स्वयंही हजम कर जाता है। इसके लिए उसके पास बहानों, कानूनी शब्दों के मायाजाल का अम्बार लगा है। यदि जनता इसके लिए न्याय मांगते हुए न्याय पालिका के पास जाती है तो वहां न्याय की देवी आंखों पर काली पट्टी बांध तराजू लिए गांधारी बन हल्का भारी करते हुए सत्ता के मोह में जकड़ी हुई पूंजीपतियों की साड़ी पहने हुए खड़ी है। उसके सामने फिर भी सिर पटक कर न्याय मांगती है और लहुलुहान होकर लौट आती है।

वर्तमान लोकतंत्र का तीसरा आधार स्तंभ पत्रकारिता है, जिसकी कलम भी पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के पास गिरवी पड़ी है, क्योंकि जनता उसे जानती नहीं, मानती जरूर है। वह भी अपना लाभ कमाने, पेट भरने और समाज में सिर उठाकर चलने के लिए धन चाहता है जो उसे षड्यंत्र कारी पूंजीपति और सत्ताधीश ही देते हैं वो उनकी चाकरी करता है। तो सच को सच लिखने, जनता के आंसू पोंछने की तो दूर झूठ को बढ़ाचढ़ाकर लिखने, दहशत फैलाने भ्रष्टों की महिमा के कसीदे पढ़ने, पढ़ाने के साथ भ्रमित करने में लगा है। इन सबके चलते लोकतंत्र कल्याण के नाम नोंच तंत्र बना जनता की पीड़ा का अधिष्ठाता बन गया ये हमारे लोकतंत्रा की व्याख्या की 62वर्ष बाद का निष्कर्ष है।

विश्व का...

शेष पेज 1 से जारी

चीनी नकली दवाएं, घातक कम्प्यूटर, खिलौने, कपड़े, बिजली, इलेक्ट्रानिक्स सामान व अन्य सामग्री जो शीघ्र खराब हो जाती, कचरा बढ़ाती विश्व बाजारों में भरी

शीघ्र ही घातक प्रभाव दिखाने लगते, लिपस्टिक, बिंदी से लेकर भारत के त्यौहारों पर लगने वाली मूर्तियों, दीवाली के फटाकों, होली के रंगों, राखी पर उपयोग की जाने वाली राखियों तक के बाजेर पर वर्तमान में चीनी उत्पादनों का कब्जा है, जो शीघ्र खराब के बाद फेंकने योग्य होते हैं। स्वाभाविक है ये कचरा न केवल भारत में वरन दुनिया के अन्य देशों की धरती पर फैलाकर पूरे पर्यावरण को तो नष्ट कर ही रहा है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर वयस्कों को भी पूरे विश्वभर में बीमारियां बांट कर मानव जीवन नष्ट करने पर तुला है। इससे पूरे दुनिया के लोग जो कमाई कर सस्ते के चक्कर में ऐसे चीन के माल को खरीदकर अपनी मेहनत की कमाई का धन बर्बाद कर रहा है।

चीनी की विद्युत सामग्री में बिकने वाले सी.एफ.एल. बाल्बों, प्लगों, ट्यूब्स, इलेक्ट्रानिक्स, आइटम्स से लेकर मोबाइल्स तक का भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो दो दिन भी चलेंगे? यही हाल पूरे भारत के साथ पूरे विश्व के बाजारों का हो रहा है, यदि मोटे अंदाज में मान लें कि पूरे विश्व में प्रतिदिन केवल इलेक्ट्रानिक्स का 10 करोड़ डालर का व्यवसाय हो रहा है
और 1 करोड़ विभिन्न उत्पादन इलेक्ट्रानिक्स के बिक रहे हैं तो स्वाभाविक है तीन से छह महीने के बाद ऐसे करोड़ों उत्पाद वे ही उत्पाद दुनिया की 2अरब आबादी के लिए परेशानी बन जाते हैं। बिगड़ते हैं टूटते-फूटते या पूर्णतः उपयोगहीन हो जाते हैं स्वाभाविक है उन्हें फेंकने से जिसमें हार्ड प्लास्टिक से लेकर घातक धातुओं की बैट्रियों व अन्य सामग्री धरती के वातावरण को बर्बाद करने, मूक प्राणियों, पशुओं तक की बर्बादी का कारण बन रही है, जिसे अभी तक पूरी दुनिया में आंका ही नहीं गया है, समयमाया के इस लेख केबाद यह मुहिम पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बेशक दो तीन वर्ष में यह बात पूरी दुनिया को समझ आएगी।

दूसरी ओर पूरी दुनिया के हर देश की चीन के माल ने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। विश्व के हर देश के बहुत सारे व्यवसायों को चौपट कर दिया और करोड़ों मजदूरों को बेरोजगार बना दिया। अमेरिका जैसे

देश की हथियारों की बिक्री के बाजार को चौपट करने से लेकर उसके लड़ाकू विमानों पनडुब्बियों, लड़ाकू जलपोतों के बाजार को भी काफी ठेस पहुंचाई है। अमेरिका जानता है, आने वाले समय में वो केवल आईसीबीएम जैसी मिसाइलें वरन परमाणुवीय क्षमता वाली मिसाइलें भी युद्ध के बाजार में बेचने से सक्षम होगा।

अमेरिका ईराक पर परमाणु बमों ओर रासायनिक बमों की आड़ में हमला करके कब्जा कर बैठा और ईरान पर भी उसकी यही नियत है। जबकि चीन के पास सैकड़ों परमाणु बम और घातक न केवल मिसाइलें हैं वरन वह भी आंतरिक्ष में घूम रहे संचार उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम है। पर अमेरिका की औकत नहीं कि वो उसके विरुद्ध आंख उठा कर भी देख सके, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर उसके अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था में भी चीन मने सेंध लगा रखी है।

वर्तमान हालात ये है कि अमेरिका की भी औकात नहीं कि उसके खिलाफ मुंह खोले, भारत की कांग्रेसी मुखैरे गिद्धों की सरकार जो जानती है कि उसकी चीन के सामने कोई औकात बख्त की तो दूर उसके शत्रुता पूर्ण व्यवहार, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का साथ ही अरुणांचल प्रदेश को वो अपने नक्शे में दिखाता है, सियाचीन ने वर्मा की सीमा तक फैली भारत-चीन सीमा में चीनी 40-50 किमी अंदर तक आते हैं। घूमते हैं जासूसी करते हैं ये जानबूझकर भी कभी उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल पाते, जबकि चीनी राजनयिक खुल कर अंटशंट बोलने से भी नहीं चूकते।

भारतीय उद्योग संघ, फिक्की ने केंद्र सरकार से चीन के हर प्रकार के माल पर रोक लगाने टेक्स लादने, उसके आयात कम करने की कई बार मांग की परंतु भारतीय विदेशी मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन भारी उद्योग संचार मंत्रालय किसी के भी कानों पर जूं नहीं रेंगी, वरन ये उल्टे ही व्यापारियों से कमीशन डकार कर अपनी अर्थव्यवस्था उद्योगों की चौपट करने मजदूरों को बेरोजगार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। वो पूरे देश को चहुंदिशि चौपट करने पर तुला है। सोनिया से लेकर मनमोहन, कमलनाथ सब चीन की यात्राएं करने और सौहार्द्र बढ़ाने का ढोंग कर रहे हैं, जबकि वे इसे भारत की नपुसंकता मान अपनी मनमानी करने पर तुला है।

दहशत के...

शेष पेज 1 से जारी

मौसमी बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी औसतन 400 प्रतिदिन हो जाती है। फिर दुनिया में 110 मौतें हर सेकंड होती है और 114 बच्चों का जन्म होता है तो फिर कमीशन की स्वींग को फ्लू की दहशत के व्यापार का मतलब तो केवल महंगाई से त्राहि-त्राहि करती जनता और पुनः राशनिंग करने के कुकर्मों पर से ध्यान हटाने की चाल के अतिरिक्त कुछ नहीं था।

आतंकी व्यवसाय बहुत ज्यादा टेड़ा-मेड़ा कानूनी दांवपेंच से मरा हुआ होने का कारण बहुत परेशानी भरा काम था, इसलिए इसे स्वींग का स्वाईन फ्लू फैलने और फैलाने के व्यसाय में कमीशन भी मोटा लचर कानून भी पंगु।

अब मीडिया की भूमिका देखिए दृश्य और श्रव्य दूरदर्शनी श्रृंखलायें तो हर वक्त नए दहशत, रोमांच, रहस्य के समाचार ढूढंती ही रहती है, ताकि अच्छा दर्शक वर्ग मिले और अच्छी विज्ञापनों से कमाई भी होती रहे, इतनी सारी श्रृंखलाओं को अपने खर्चे निकालने और लाभ कमाने के लिए हर वक्त मुद्दों की तलाश रहती है, जो दर्शकवर्ग में दहशत, सिहरन, भावनाओं का तूफान मस्तिष्क में पेंच कुछ तीखा सेक्सी, अंदाज, नग्नता, फूहड़ता, उत्तेजकता पैदा करें, नहीं तो इसके विपरीत डर, भय,अवसाद, अर्थात कुछ नया पैदा करे चाहे उससे दर्शकों की मौत हो जाए। दर्शक आत्महत्या कर लें तो सब चलेगा पर बस कछ अलग हटकर हो, फिर स्वाइन फ्लू हो, आतंकवादी घटनाएं, हो दुर्घटनाएं हो जानी, मानी हास्तियों की नग्नता हो, सब चलेगा। ट्यूबवेल में गिरा हुआ बच्चा हो दर्द से तड़पती जच्चा हो, एस.एमस.एस. करके दुआ मांगने का बहाना हो, घर में बैठी महिलाओं और बच्चों को लुभाना हो, सहानुभूति दिखाने, आंसू बहाने का बहाना हो, इन्हें तो एस.एम.एस. से पैसे कमाना है में ये मीडिया के धूर्त दर्शकों को दूर से दर्शन करवा कर उलझाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस इस खेल की सिद्धहस्त खिलाड़ी है। इन्हें नोटों की हरियाली दिखाकर नचाकर अपना मतलब सिद्ध करने में सिद्धहस्त अपने कुकर्मों को ऐसे दबा देती है।

सबसे महत्वपूर्ण देश के कांग्रेसी गिद्ध प्रधानमंत्री को देखिये जो हरामखोर पहले देश के कृषि उत्पादनों को सस्ता खरीदकर किसानों से पहले ऊंची कीमतों पर कमीशन डकार कर निर्यात करवा कर पहले देश में कमी पैदा करते हैं। फिर कमीशन डकारने के लिए सड़ा सस्ता खरीदकर उसे भी जनता से टपका और भूखा मार राशन की दुकानों से महंगा बिकवाते हैं और चिल्लाते हैं प्रधानमंत्री होने के बाद भी महंगाई तो बढ़ेगी ही बहाना कोई सा भी हो।

नेताओं के नाम पर कलंकी प्र.मं. मनममोहन उसकी अम्मा सोनिया और पूरा गिरोह की नीचता देखिए जो देश के शीर्ष पर बैठकर मात्र अनी कमाई के लिए जनता को दहशत बांट रहे हैं। जिन्हें जनता को खुशी बांटने के लिए बैठाया था आंसू बांट रहे हैं और कह रहे हैं पूरे मत बहा देना, हमारे बैठने तक ऐसे ही बहाने पढ़ेंगे रो-रोकर जियों और हमें वोट देते रहे।

राष्ट्रगीत गुलामी का

शेष पेज 1 से जारी

गीत गुलामों की तरफ से वंदना में लिखा था, जिसे स्व. मोतीलाल नेहरू की पीढ़ी जो इंग्लैंड में पली पढ़ी हुई थी जिसमें स्व. जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार था ने अपनी चरित्रहीन पुत्री स्व. इंदिरा गांधी जिसे शांति निकेतन में पढ़ाया था के कर्मकांडों को दबाने, स्व. रविन्द्रनाथ टेगौर का मुंहबंद रखने के लिए इसी गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित कर रविन्द्रनाथ टेगौर को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कर दिया था, ताकि रविन्द्रनाथ टेगौर द्वारा स्व. इंदिरा की अय्याशी के चर्चे सार्वजनिक न हो जाए। अपनी बेटी को बचाने के लिए चली धूर्त की इस चाल को पूरा देश तन से भले ही गुलाम न दिखे पर मन से गुलाम होकर जरूर भोग रहा है।

पूर्व की केंद्र की भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार ने इस पीड़ा को समझकर ही वंदे मातरम को स्वीकार किया था। निःसंदेह भाजपा की म.प्र. सरकार भी इसे ही राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकार कर कार्यालयों में वंदे मातरम का ही गान गाती है। कैसा है जनता के चुने गणों का तंत्र, जो अपना दिवस मनाता है पूरे वर्ष 120 करोड़ लोगों से गुलामी के गीत गवाता है। अधिनायक के जयकारे लगवाता है, जागो 120 करोड़ जागो, गुलामों, हजारों वर्ष की गुलामी त्यागो अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया पर राज करके दिखाओ।

मप्र में बिजली की 3 से 14% तक कीमतों में बढ़ोतरी

निजी क्षेत्र में देने तथा विद्युत केंद्र किये जा रहे बंद

समयमाया ने अपने फरवरी 09, मार्च 09 के अंकों में विद्युत मंडल की जालसाजियों और बिजली बेच कर प्रदेश की जनता को परेशान कर बिजली की कीमतें बढ़ाकर जनता को लूटने की तैयारी में विस्तार से लिखा था।

जुलाई के बजट सत्र में बिजली की उसे 14% कीमतें बढ़ा कर म.प्र. की शिवराज की भाजपा सरकार ने उसे सही सिद्ध कर दिया है। अब जनता यह मान कर ही चले कि उसकी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण के लिए नहीं वरन स्वकल्याण के लिए देश-प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात कर कमाई करने के लिए बैठाई जा रही है। चाहे वह कांग्रेसी गिद्धों का गिरोह हो या भाजपाई डकैत।

हमारे भारत में 2008-09 की मंदी का असर इसलिए ही नहीं था कि हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था साम्यवाद और पूंजीवाद का मिश्रित व्यवस्था होने के कारण विश्व में हम सिर उठाकर चल सके थे, पर डकैतों का धर्म डकैती डालकर घर भरना और गिद्धओं का धर्म जिंदा या मुर्दों को नोंच खाना है। वो भूल गए इसलिए अपनी औकात पर लौट आए और पूंजीपतियों की कठपुतली नाचते हुए उन्होंने निर्णय कर लिया है कि सारी विद्युत उत्पादन व्यवस्था निजी पूंजीपतियों को सौंपकर उनसे खरीदी में भी कमीशन डकारें, मोटा। इसलिए जानबूझकर संजय गांधी क्षमता 1340 मेगावाट, सतपुड़ा 11425 मेगावाट और अमर कंटक 450 मेगावाट को पूरी क्षमता से नहीं चलाया जाता साथ ही सदा कोई भी कारण बताकर इनकी कई इकाइयों को बंद रखा जाता है। ताकि विद्युत आपूर्ति के बारे में जनता को दिखाया, बताया जा सके कि मंडल तंग हाल है, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। जबकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कीमतें बढ़ाने के बाद भी आपूर्ति और मांग का संतुलन व सामंजस्य नहीं बैठाया जा रहा है। कीमतें बढ़ाने के बाद क्या पूरे प्रेदश में 24घंटों तक आपूर्ति हो रही है, वह तो कदापि नहीं, तो फिर हरामखोरों से पूछो कि ऊर्जामंत्री अनूपमिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज, मुख्य सचिव राकेश साहनी व अन्य सभी षड्यंत्रकारी डकैत कीतमें बढ़ाने के बाद 24घंटे आपूर्ति देने में असमर्थ हो तो उसे 14% की दर बढ़ाने का औचित्य क्या है। या केवल बढ़ाई कीमतों को जनता से नोंच कर सीधा डकारना ही उद्देश्य है।

म.प्र. विद्युत मंडल की साइटों से लिए गए आंकडें है इस संबंध में उनका अवलोकन करें जो इनकी धूर्तता का खुला कच्चा काला चिट्ठा है-

सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की इकाई क्रमांक 3 जो 62.5 मेगावाट क्षमता की है प्रातः 9.25 मि. से 15-7-09 से, इकाई क्रमांक-7 जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है 4:25 प्रातः 30-7-09 से बंद है। अमरकंटक की इकाई क्र. 4 क्षमता 120 मेगावाट प्रातः 1.05 से 21-07-09 और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की 23:57 बजे से 1-8-09 से बंद पड़ी है। अर्थात कुल ताप विद्युत की 2932.5 मेगा क्षमता का 10/25 मेगावाट क्षमता कोई माप के कम दबाव, कोई तेल के कम दबाव से कोई किसी कारण से जानबूझकर बंद रखी गई है। जबकि अमर कंटक में 3 अगस्त को कोयल 57,744 टन, सतपुड़ा में 5,44719 टन और बीर सिंगपुर में 46018 टन कोयला उपलब्ध था, बेशक 25% स्टाक के आंकडे फर्जी हैं। कोयला ट्रकों से लाते समय बीच में बेचकर डकार लिया गया, गेट कीपर को रुपए 100 दिए और 15फंट कोयले का 11'-11' की कोयला प्रति ट्रक अंदर पहुंचा। कोयले की अवैध बिक्री में गेट कीपर से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके हाथमुंह काले हैं।

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अपने हिस्से के साथ जो जल और ताप विद्युत एनएचडीसी, एनटीपीसी से खरीदी गई थी उसका भुगतान जुलाई में अवश्य किया गया। इसके विपरीत टाटा व अन्य निजी कंपनियों से खरीदी बिजली का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इनकी साइटें बताती हैं कि संभागीय स्तर पर ये 23 घंटे बिजली दे रहे हैं, जबकि वास्तविकता में सुबह 6.30 से 8.30 बजे तक 2 घंटे कटौती कर रहे हैं। जिलास्तर पर 21 घंटे, वास्तविकता में देवास, शाजापुर, धार जैसे प्रदेश के 40 जिलों में मात्र 12 घंटे और ग्रामीण में 3फेस और 1 फेस 3 से 5 घंटे मुश्किल से आपूर्ति दी जा रही है। 22 घंटे बिजली मात्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में मिल रही है, जबकि उज्जैन, सागर, रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, श्योपुर में 20 घंटे ही आपूर्ति की जा रही है। **शेष पेज 5 पर**

आबादी ६ करोड़, दुधारू पशु २ करोड़ भी नहीं, दूध, घी, तेल, मसाले सभी मिलावटी

सभी मिलावटियों, सरकारी स्वा.वि., नपा, निगमों के निरीक्षक

म.प्र. में ग्वालियर संभाग से किए जा रहे मावे की आपूर्ति, नकली घी के कारखाने पूरे प्रदेश के हर जिलों में पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा चल रहे हैं। अधिकांश खाद्य वस्तुओं, दूध, घी, दही, मिठाइयां, नमकीन, मसालों, खाद्य तेलों पैकेट, फूड में बिस्कुट, गोली, चाकलेट, आइसक्रीम सभी मिलावटी हैं। म.प्र. के पूरे खाद्य एवं औषधि विभाग के सारे खाद्य निरीक्षक न केवल भ्रष्ट वरन दुकानदारों से वसूली न होने पर नमूने लेने के बाद भी अगर सौदा हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो अगर प्रयोगशाला में भेज भी दिया तो इसी विभाग से पिछले 5वर्षों से ज्यादा समय से सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक जो अब हरामखोर जैसे पूर्व का इंदौर का खाद्य निरीक्षक पचौरी जो न केवल अभी भी वसूली कर रहा है, वरन नमूने चाहे इंदौर, म.प्र. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत खाद्य विभाग के निरीक्षक ले या नगर निगम के खाद्य निरीक्षक लें सारे नमूने भोपाल की म.प्र. शासन की खाद्य प्रयोगशाला में हैं जांचे व प्रमणित किए जाते हैं जहां लोक विश्लेषक आर.पी. मिश्रा बैठा है, के साथ सांठगांठ क़रके प्रति नमूना रुपए 10 से 25 हजार में पास करवाने के ये न केवल सेवानिवृत्त बल्कि पूरे प्रदेश में कार्यरत 200 से ज्यादा खाद्य निरीक्षक भी धन देकर उसे मानक स्तर का प्रमाणित कर लेते हैं। इसलिए 90% नमूने म.प्र. की खाद्य प्रयोगशाला से पूरे प्रदेश केा मानक स्तर के घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि आम नागरिकों और अधिकारियों, डॉक्टरों से लेकर खाद्य व ओ.वि.के निरीक्षक तक जानते हैं कि बाजार में 90% खाद्य मिलावटी बिक रहा है।

खाद्य व औ. वि. के निरीक्षकों को नमूने लेने के बा जो हर जिले के म.प्र. स्वा एवं चिकित्सा विभाग के मुख्य जिला चिकित्साधिकारी जो इस विभाग का उपसंचालक होता है से हस्तांक्षरित पर्चियां लेने पड़ती हैं। ये हरामखोर मु.जिला चि. अधिकारी उन पर्चियों पर हस्ताक्षर करने और पर्चियां जारी करने के भी पैसे लेकर ही पर्चियां जारी करते, विभागीय निरीक्षकों के साथ नगर निगमों और पालिकाओं के खाद्य निरीक्षकों को इंदौर में ही गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार खा.नि. सचिन लोंगरिया व खाद्य निरीक्षक ज्योति व एक अन्य ने दिए तो इस हरामखोर मु.चि. अधिकारी शरद पंडित ने उन्हें नमूना लेने के लिए पर्चियां ही नहीं दी। डॉ. शरद पंडित की नीचता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मिलावटियों को शूकर धन लेकर बचा लेता है।

इंदौर में कार्यरत खा. नि. जिसमें खा.नि. भैरोसिंह जामोद सुरेंद्र ठाकुर, शैलेष गुप्ता, मनीष स्वामी, वैशालीसिंग सुभाष खोड़कर अमित वर्मा, ज्योति बघेल, सचिन लोंगरिया है। को हर महीने 10 से 15 नमूने लेने चाहिए, अर्थात यदि ये सारे खा.नि. कानूनानुसार नमूनें लें 90 से 135 नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए, इस हिसाब से म.प्र.में 235 खाद्य निरीक्षक हैं, नियमानुसार पूरे प्रदेश से 2350 से 3000 नमूने प्रयोगशाला में जाने चाहिए, परंतु अधिकांश हरामखोर महीने भर नमूनों की आड़ में वसूली में जुटे रहकर वसूली करते रहते हैं। यही हाल प्रदेश के 48 जिलों की नगर पालिकाओं, निगमों के साथ तहसील स्तर की पालिकाओं, परिषदों में कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा निरीक्षक भी विशुद्ध वसूली में जुटे रहकर जिन्हें 5 नमूनाप्रति निरीक्षक के हिसाब से 10,000 नमूने जाने चाहिए, तो हजार नमूने भी नहीं भेजे जाते, क्योंकि निगमों और पालिकाओं ग्वालियर, उज्जैन के साथ पूरे प्रदेश में पार्षद निगम अधिकारी और निरीक्षक करते आ रहे हैं।

इंदौर में ही सैकड़ों टन मावा, घी, दूध, मसाले पकड़े गए, जब्त करके नष्ट करने की नौटंकियां तो खूब होती है, परंतु नमूने भोपाल नहीं भेजे जाते, नमूना भेजने की बात उठती है, तो नमूने हजारों का सौदा करके बदल दिए जाते हैं। यदि नमूने अवमानक पाए जाने की रिपोर्ट आ भी जाती है तो सीएमओ प्रकरण लगाने की अनुमति देने से पूर्व ही दोनों जेल में सड़ जाएंगे। बेशक सुषमा पथरोल की तरफ से अरविंद पथरोल ने एडीएम, सीएमओ भंडारी जो प्रभार में था से जालसाजीपूर्ण कारनामों के लिए कई बार रुपए 20हजार की गड्डियां थमाने के समाचार हैं।

व्यापारी, निरीक्षक स्वा.वि. निगमों पालिकाओं में बैठे सबको चाहिए धन जनता मरे तो मरे

में 90% खाद्य निरीक्षक वहीं के क्षेत्रीय निवासी होते हैं, जिनके संबंध वहां के क्षेत्रीय पार्षदों, दुकानदारों से रहते हैं। स्वाभाविक सबसे महीना वसूली होती रहती है। क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त किए गए निगमों, पालिकाओं में खाद्य निरीक्षकों की भर्ती हो जालसाजीपूर्ण तरीके से वहां बैठे अधिकारी, पार्षद अपने लोगों, भाई-भतीजों को नियुक्त करवा देते हैं, जिनके पास आवश्यक शिक्षा भी नहीं होती, पूरे प्रदेश में ऐसे 50% ज्यादा खाद्य निरीक्षक है, पालिकाओं और निगमों में स्वाभाविक उनके गजट वैरीफिकेशन भी नहीं होते हैं, नगरनिगम इंदौर में इस संबंध में सूचना अधिकार में पत्र दिया गया था,हरामखोर, जालसाज मिलावटियों स्वास्थ्य अधिकारी और निगमायुक्त ने न केवल 9-10 में से केवल तीन के गजट मोटीफिकेशन की ही कापी दी, अब यदि येहरामखोर नमूने अवैधानिक तरीके से ले भी लें तो मात्र वसूली के और धमकाने के लिए। फिर पूरे प्रदेश में निगमों, पालिकाओं के ये मिलावटी जालसाज खाद्य निरीक्षक 95% नमूने लेकर पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के आपसी बदले की भावना से लेते हैं। वास्तविक मामलों में लिए 95% नमूने जहां से लिए जाते हैं उन दुकानदारों, फैक्ट्रियों, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ता कहीं न कहीं पार्षदों, निगम कर्मचारियों, अधिकारियों से कहीं न कहीं जुड़े होने, चंदा देने, विज्ञापन देने जो नेताओं को लिए छपवाए जाते हैं खर्च उठाते हैं तो ऐसे 95% मिलावटी नमूनों की कानूनी दांवपेंचों में उलझाकर ऐसे मिलावटी अधिकारी, निरीक्षक पार्षद उन्हें बचा लेते हैं। जैसा कि पिछले दस वर्षों से इंदौर, भोपाल, लेनदेन करके मामला रफादफा कर लेता है। या खाद्य निरीक्षक ही मिलावटिये में हरामखोर रिपोर्ट दबा लेते हैं जैसा कि इंदौर में खा.नि. जामोद, स्वामी व अन्य कर रहे हैं। देवास में बैठी जालसाज, मक्कार, भ्रष्ट श्रीमती सुषमा पथरोल और उज्जैन में बैठा उसका पति खा.नि. अरविंद पथरोल पिछले तीन वर्षों से कर रहे हैं, ये दोनों दम्पत्ति ने मिलकर पिछले 3वर्षों से ज्यादा समय के अल्पकाल में ही करीब 1 करोड़ कमाए, सैकड़ों नमूने फेल होने के बाद भी उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, अपने तो इन दोनों जालसाजों ने अपने नमूने या तो भेजे ही नहीं और भेजने के बाद भी नमूने अवमानक पाए जाने पर भी रिपोर्ट को ही दबा कर लाखों की वसूली कर रिपोर्ट्स भी लेकर घव पर रख ली और वो समय बाधित हो गए, अब जबकि उज्जैन और देवास में 5-5 खाद्य निरीक्षक हो चुके हैं। दूसरे खाद्य निरीक्षकों ने जो नमूने ले भी लिए तो इ खा.नि. अरविंद और सुषमा ने ले जाकर घर रख लिए। यदि किसी प्रकार खाद्य निरीक्षकों ने खानापूर्ति के लिए भेज भी दिए और अवमानक मिथ्या छाप की रिपोर्ट आ भी गई तो रिपोर्ट ही दबा ली, नहीं तो तीन मामलों में इस खा.नि. सुषमा ने अपात्र विद्या बेल्हणकर से जो कि सहायक संचालक थी हस्ताक्षर करवा कर पेश किए तो न्यायालय ने सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के अभाव में स्वीकार करने से ही मना कर दिया ये है इन हरामखोर, मिलावटी श्वानों की वसूली की करतूतें। म.प्र. लोकायुक्त अरविंद और सुषमा पथरोल के कारनामों को ही जांच कर लें तो

म.प्र. खाद्य व औषधि नियंत्रक ही भ्रष्ट हों, मिलावटी हो तो नीचे वालेतो फिर सारे मिलावटियों से वसूली करेंगे ही, क्योंकि न ही लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर नियंत्रक प्रदेश के लगभग 250खाद्य निरीक्षकों से स्पष्टीकरण नहीं मांगता कि कितने नमूने अवमानक, मिथ्या छाप घोषित हुए कितने न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, लोक विश्लेषक आर.पी. मिश्रा पर उसकी प्रयोगशाला पर लोकायुक्त क्यों हीं छापामार कार्यवाही करके षड्यंत्र कि हर माह हजारों की संख्या में पहुंचने वाले नमूनों की जांच किस स्थिति में है प्रयोगसाला के कर्मचारियों और लोकविश्लेषक मिलावटी नमूनों को पास करने के रुपए 5 से 50 हजार तक वसूलता है। 90% मिलावटी नमूने होने के बाद भी 90% नमूने पास होने का कारण है हर स्तर पर लेनदेन अर्थात लोक विश्लेषक करोड़ों का खेल रहा है।

दूसरी ओर दूध व दूध से बने उत्पादों के मामले में 6 करोड़ की आबादी वाले पूरे प्रदेश में दो करोड़ पशु भी नहीं हैं। 50 लाख दुधारू पशु कैसे करोड़ की मांग पूरी कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है। सांची दूध के नमूने पूरे प्रदेश में 10 से ज्यादा वर्षों से नहीं लिए गए हैं। यह प्रश्न म.प्र. की विधानसभा के बजटसत्र में भी गूंजा था पूरे प्रदेश से सूचना के अधिकार में दिए पत्र में प्राप्त जानकारी में कई मिलावटी खाद्य निरीक्षकों ने झूठी जानकारी दी कि नमूने लिए गए थे पर स्तरीय थे।

म.प्र. में हाल ही में नियुक्त लगभग 200 खाद्य निरीक्षकों ने आते ही हरामखोरों ने वसूली शुरू कर दी है। जिसमें महिलाएँ कुछ जरूरत से ज्यादा ही न केवल गुल खिला रही हैं, वरन अपने कोमलांगी और महिला होने का भी भरपूर फायदा उठा कर दोनों हाथों से वसूली कर रही हैं। जैसा कि देवास की खाद्य नि. सुषमा पथरोल के बारे में प्रकाशित पूर्व के ओर उपरोक्त जानकारियां सिद्ध कर रही हैं। इनके सामने सी.एम.ओ., एटीएम, एसडीएम भी बोने पड़ रहे हैं। हरामखोर कुकर्म भी करती है, बाद में फंस जाने पर रो-रोकर सहानुभूति बटोर कर बच निकलने में भी कामयाब हो जाती है। इनकी बला से जनता कल की मरती आज मरे।

साप्ताहिक
समय माया

वन विभाग में चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव

प्रकृति, वनैले शूकरों की भांति उजाड़ने की दावा हंस होने का

शासकीय आबंटित धन और वन सम्पत्तियों की नोंच खसोट

म.प्र. के वन विभाग में चारों तरफ चल रहा है केवल झूठे व्हाउचरों, से शासन के धन डकारने और झूठे आंकडों की बाजीगरी का खेल इंदौर के अखबारों को लें तो हर सप्ताह में इंदौर और आसपास के जंगलों में चल रही अवैध कटाई जंगल की भूमि पर कटाई करके साफ की गई भूमि पर अवैध कब्जों और पट्टे बांटने में लाखों रुपए का लेनदेन यह कहानी केवल इंदौर की ही नहीं, देवास, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, बड़वानी, झाबुआ, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीहोर आदि पूरे प्रदेश में है। इंदौर के डीएफओ वर्तमान में इन्हें वन संरक्षक बना दिया गया है। हर बार जब भी जंगल कटने, वन भूमि पर अतिक्रमण अवैध कब्जों, वन पशुओं, मोर, पक्षियों के दाना, पानी वन ग्रामों के विकास वन सुधार, मार्किंग, वन विकास, वन भूमि पर सड़कें पुलियां, मजदूरों पशुओं के पीने के लिए पानी के तालाब आदि के नाम पर हर जिले के संभागीय कार्यालयों में शासन करोड़ों रुपए स्वीकृत करते हैं। इन सबमें संभागीय कार्यालय के अंतर्गत चलने वाले सारे रेंज आफिसों में रेंजर्स इन सबके नाम पर हर महीने लाखों रुपए के झूठे व्हाचरों को लगाकर आराम से 50 से 80% पैसा एक तरफ शासन का डकार जाते हैं। दूसरी तरफ इनके रेंज में आने वाले वनों में लगी कीमती इमारती पेड़ों की अवैध कटाई करवा कर प्रति वृक्ष रुपए 1000 से 5000 तक डकार कर बिकवाते रहते हैं। तीसरी तरफ इनके वन क्षेत्र में लगे दुलर्भ जड़ीबूटी के वृक्षों, फसलों, जिसमें आंवला, हर,बहेडा, कत्था, नीम की निम्बोलियों से लेकर पुंआर की जंगली पेड़ों के पत्तों से लेकर बीजों जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी में मिलाने वाली चिकोरी के नाम से बिकते हैं रुपए 2प्रति कि. का माल रुपए 50 से रुपए 100 तक बिकता है। रोषाधांस का तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए 5000 से रुपए 10000/- प्रति कि.ग्राम तक बिकता है। ऐसी सैकड़ों वनोषधियों का व्यापार ये जालसाज बीट गार्डस से लेकर रेंजर्स वनपाल की डीएफओ और वन संरक्षक तक बाले-बाले करकर करोड़ों रुपए डकार जाते हैं।

इंदौर का एफओ कृष्णामूर्ति से जब-जब इन अनिमितताओं की बात या पूछताछ की जाती है तब ये हरामखोर हरा बार जो टालमटूली वाले जवाब देता है, इस हरामखोर निकम्मे को नहीं दिखता कि इंदौर के टिम्बर मार्केट धार रोड पर हरा सुबह 30 से 60 ट्रक, ट्राले, मिनी मेटाडोर भरकर हरी-हरी लकड़ी कहा से आती है। जबकि वहां नियुक्त रेंजर हर महीने हर टिम्बर व्यवसायी से महीना वसूल कर वहां लकड़ी के आवक-जावक रजिस्टर में खानापूर्ति करके काम चला रहे हैं। स्वाभाविक है ये लकड़ी इंदौर के 200 किमी के क्षेत्र में जिसमें देवास, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, शाजापुर, रतलाम क्षेत्र से जो कटाई का जीता है वही सारे नाको पर पैसा बांटकर यहां तक पहुंचाती है। आखिर इंदौर-उज्जैन के टिम्बर मार्केट और हर शहर में लगी आरा मशीनें और फर्नीचर व्यावसाइयों की दुकानदारी इसी लकड़ी के दम पर ही तो चल रही है। फिर भोपाल का विआई एमपी-3 की गाड़ी में अवैध लकड़ी भरने आया और उसको छोड़ दिया गया। गुर्जर रेंज के पास रुपए ढाई करोड़ की सम्पत्ति पकड़ी गई तो क्या आसमान से टपकी थी। समयमाया के पास देवास के वन मंडल की रोकड़ बही व अन्य दस्तावेज सूचना के अधिकार बड़ी मुश्किल से पचासों चक्कर काटने के बाद दिए गए, वो ऊपर लिखे हर बात का दस्तावेजी प्रमाण है।

देवास वन मंडल में नोरेंज कार्यालय है हर महीने इन हरामखोरों को वन ग्रामों, वनों के विकास पशुओं के दाना पानी, वनों में कार्यरत मजदूरों, सड़कों, बिगड़े वनों का सुधार सुधार कार्य, कर्मचारियों, अधिकारियों की वर्दी या वायरलेस सेट की खरीदी सुधार, मोबाइल की खरीदी सुधार, आकस्मिक व्यय, गाड़ियों में तेल, पेट्रोल, सुधार, रखरखाव, पथ निकासी, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायत्रियां, परिवहन व्यवस्था, मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण, केपं कुटीर स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण डिक्री धन का भुगतान, जन संसाधनों का सर्वेक्षण कार्य, सहायता अनुदान, हिंसक पशुओं के विनाशक के लिए पुरस्कार वन अपरोधों का पता लगाने हेतु पुरस्कार गोपनीय सेवा व्यय, वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति, मजदूरी में भी कई अलग-अलग मदों में भुगतान, जिसमें सामान ढोने, विद्या वनों का विकास, पर्यावरण पार्कों का विकास, मुनारा निर्माण, सुधार कार्य, कापिस विद रिजर्व रखरखाव, पौधा तैयारी कार्य, वृक्षारोपण तैयारी कार्य बाउंड्रीवाल तैयारी, सघन गश्तों के माध्यम से वन सुरक्षा वनों की आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना, मजदूरी लाईन क्वार्टर, मजदूरी राज्य आयोजना की लोकवानिकी मजदूरीकृत स्तरीय कार्यशाला, वन चौकी मजदूरी के आदि के नाम से करोड़ों रुपए के झूठे व्हाउचरों से रेंजर्स से लेकर डी एफओ सीएफ करोड़ों रुपए की बंदरबांट डकार जाते हैं।

देवास क्षेत्रीय वन मंडल की रोकड़ पुस्तिकाओं के अध्ययन से निकाले गए निष्कर्षों के अनुसार अगर मात्र 06-07, 07-08 और 08-09 खर्च किए शासकीय धन के दुरुपयोग और झूठे व्हाउचरों से डकारे गए धन की शिकायत जो उपरोक्तानुसार दर्शायी गई मदों में खर्च किया और करोड़ों रुपए के झूठे व्हाउचरों से धन डकारा गया। मजदूरी में हर मद में 40% से 60% विकास कार्यों वन ग्रामों के विकास कार्यों के नाम 30 से 50% से विशुद्ध पैसे रेंजरों और डिप्टी रेंजरों, कार्यालयों के बड़ा बाबू, लेखा पाल से मिलकर वन मंडलाधिकारी की जांच लोकायुक्त और ईओब्ल्यू कोसों दी जाए तो पिछले तीन वर्षों रुपए 15-20 करोड़ के घोटाले में डूबी भ्रष्टाचार की रकम में 90% के ऊपर लोकायुक्त आरोप पत्र देने में सक्षम है। अकेले नान प्लान 08 में आवंटित रुपए 4 करोड़ लाख में से रुपए 65 करोड़ 3 लाख खर्च और प्लान में आवांटित रुपए 8 करोड़ 76 लाख में से खर्च 8 करोड़ 2 लाख में से रुपए 5 करोड़, झूठे व्हाउचरों के सहारे डकारा गया, अर्थात रुपए 14 करोड़ 75 लाख में से रुपए 6 करोड़ की बंदरबांट कर ली गई, क्योंकि नाम प्लान में मोटा बजट वेतन में खर्च हो जाता है। इसी प्रकार सिवनी अमयारण्या, कन्नौद क्षेत्र का देवास को आबंटित रुपए 82 लाख 98 हजार में से रुपए 75 लाख 86 हजार में रुपए 30 लाख के लगभग डकार लिए गए यही हाल पूरे म.प्र. के हर जिले के वन विभाग का है।

जहां शासन से प्राप्त नान प्लान में 20 से 30% और प्लान में 30 से 50% सीधा डकारा जा रहा है। इसके साथ ही वनों की लकड़ियों की कटाई, जड़ीबूटियों, वार्षिक फलों, फसलों, पत्तो व अन्य वनोपजों की अवैध बिक्री का कारोबार भी जिसमें जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों के शिकार से भी लगभग रुपए 5 से 10 करोड़ का कारोबार किया जा रहा, जमीनों के अवैध कब्जों और बाद में पट्टा वितरण भूमि पर अवैध कब्जे उस पर मकान, फैक्ट्रियों, वन ग्रामों के वैध-अवैध विकास में भी हर वन मंडलाधिकारी करोड़ों रुपए अवैध कारोबार से भी कमाते हैं। अगले अंकों में पढ़िये बिन्दु बार मदबार वसूली और भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा जो कि प्रदेस के हर वनामंडलाधिकारी चाहे वह नियमित हो उत्पादन वनों के विकास आदि में हो, कैसे लूटपाट की जा रही है फिर भी डीएफओ रेंजर, वन संरक्षक अपने आपको वनैले शूकर होने के बाद भी हंसों की तरह श्वेत धवल पाक साफ बताते हैं।

श्रीलंकाई ड्रेस में...

शेष पेज 1 से जारी

श्रीलंका में प्र.मं. मनमोहन और उसकी आका सोनिया ने भारतीय सेना को ठीक चुनाव की घोषणा के उपरांत भेजकर हमारे देश की जनता जो श्रीलंका में जाकर बस गई थी पर भीषण नरसंहार करते हुए बमों, गोलियों, टैंकों आदि का खुलकर प्रयोग किया गया।

जिस लिट्टे को भारतीय सेना ने मारा, उसी लिट्टे को स्व. राजीव गांधी की चालबाजियों के चबलते पालपोसकर खड़ा बड़ा किया गया था। धन हथियार सब भारतीय सेना के ही थे। बाद में 1988-89 में लिट्टे के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए जब बारतीय शांति सेना ने लिट्टे के विरुद्ध जो दमनचक्र चलाकर उस वक्त भी निहत्थों पर भी गोलियां चलाकर हवाई हमलों में भूना गया था के बदले में जब स्व. राजीव गांधी की हत्या कर दी गई उसका बदला इन्होंने लाखों निरीह तमिलों को मारकर लिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ, एम.नेस्टी इंटरनेशनल विश्व मानवाधिकार परिषद् को भारतीय सत्ता के इन दोनों धूर्तों सोनिया और प्रधानमंत्री मनमोहन का ये भीषण नरसंहार किसी को नहीं दिखा, जिसमें लाखों निरपराधों को मौत के घाट उतारा गया। 3 से 5 लाख लोगों को बेघरबार कर सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, कहा गया अमेरिका दुनिया की रहनुमाई करने वाला विश्व का दादा सब क्यों चुप हैं? बेशक संयुक्त राष्ट्र संघ और एमनेसी इंटरनेशनल ने ही ये रिपोर्ट

अपनी इंटरनेट साइट पर डाली थी कि वास्तविकता में श्रीलंकाई सेना ने नहीं वरन भारतीय सेना के ही अधिकांश सैनिकों को श्रीलंका ड्रेस पहनाकर भारतीय सेना ने ही सारा भीषण नरसंहार किया। इसके बारे में समयमाया ने अपने 15-6-09 से 23-6-09 के पत्र में काफी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। इसके बारे में सेवा निवृत्त मेजर जन. अशोक मेहता ने भी कहा था कि कैसे भारतीय सेना ने अपनी जनता की रक्षा के विपरीत भीषण नरसंहार कर लिट्टे और लाखों तमिलों को भूनकर समुद्र में फेंक दिया। तमिलनाडु का मुख्य करुणानिधी सब जानकर भी केवल घड़ियाली आंसू बहा रहा है और बदले और अपने बेटे के साथ अन्य सदस्यों को भी भारत सराकर में मनमोहन, सोनिया और पूरी कांग्रेस की ब्लैकमेल कर मंत्री पद दिलवाने में सफल रहा।

आश्चर्य इस बात का है कि देश में लोकसभा का पूरा बजट सत्र पूरा हो गया पर कोई भी 540 लोकसभा सदस्यों में से उत्तरी बारत का तो छोड़ भी दें तो दक्षिण भारतीय सांसद भी लोकसभा में इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछ सका। बेशक कांग्रेसी मनमोहन, सोनिया ने सबको पैसा बांटकर मुहं पर ताले डाल दिए। इन सबके विपरीत समयमाया न केवल भारत की जनता वरन संयुक्त राष्ट्र संघ एमनेस्टीइंटर नेशनल, विश्वमानवाधिकार परिषद् से ये अपेक्षा करता है कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मनमोहन, सोनिया पर देश में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकद्मा चलाया जाए और इनकी असलियत दुनिया के सामने लाई जाना चाहिए।

२०० करोड़ से ज्यादा

शेष पेज 8 से जारी

कार्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्राम साफ्टवेयर की सीडी बेचकर व बिकवा कर वो 10,0000 करोड़ अमेरिकी डालर कमा सकें, उसके पक्ष में सरकार कानून बना दे, ताकि वो अपने साफ्टवेयरों की असली सीडी या आनलाइन प्रोग्राम साफ्टवेयर बेचकर रुपए 1 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का व्यवसाय के बहाने पूरे देश के निजी व्यावसायिक स्तर पर बेचकर कमा सके, वही हुआ वो दानी, धर्मी नहीं एक नं. का महानीच राक्षस है जो अरबों डालर पूरी दुनिया से चाहे वो चीन, फ्रांस, भारत, उत्तरीकोरिया, ईराक, ईरान, तक से नोंच खाता है। इंटरनेट के कारण उसका व्यवसाय क्षेत्र पूरा विश्व है। उसे राष्ट्रों, महाद्वीपों की सीमा कोई मायने नहीं रखती।

आखिर क्या करेगा दानी, धर्मी होने का नाटक करने वाला ये महादैत्य कितना खाता है तो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1 किलोग्राम इसे तो चीन, उत्तरी कोरिया, रूस, ईरान जैसे देश अपने यहां बुलाकर गिरफ्तार कर पूरी दुनिया कम्प्यूटर वायरस भेजकर सारे व्यक्तिगत स्तर से सरकारों, जनता को नोंचने के लिए परेशान करने वाले इस धूर्त को जीवन भर कारावास में सड़ाया जाना चाहिए। जहां तक भारत का सवाल है तो यहां तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सारे मुखैरे टुकड़खोरों की फौज है जो टुकड़े मिलते ही पूंछ हिलाने से लेकर उस नीच राक्षस बिल गेट के लिए कानून बनाने, न्यायालयों में मुकदमें चला कर दो वक्त की रोटी कमाने वालों को भी जेल में भेजने से नहीं चूकती। बेशक यह बात सच है कि केंद्र व राज्य सरकारें अरबों रुपए अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभागों पर खर्च करती है उन्हें भारत संचार निगम लि., एयरटेल, टाटा, रिलायंस को साथ लेकर ऐसे कम्प्यूटर वायरसों को सरकारी स्तर पर रोकना चाहिए, पर ये सारे तो स्वयं बिलगेट के तनखैय्या और कमीशन खोर हैं। इनसे ये उम्मीद निरर्थक है।

खोदे, खोजे...

शेष पेज से जारी

जबकि जिस कावेरी-गोदावरी बेसिन के ब्लाक में 2 अरबघन मी. गैस का आकूत भंडार पाया गया है उसे खोदा और खोजा भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने सन 2000 के पहले था। इसके बाद अरबों रुपए का लेनदेन होने के कारण उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री, प्रधानमंत्री और निगम के अधिकारियों ने उसे बंद कर दिया। उसके बाद यह जमीन पट्टे पर रिलायंस के धीरू और उसके बेटों, अनिल और मुकेश ने उस पर कब्जा जमा लिया और बाद में संयुक्त उपक्रम भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ स्थापित कर अभी नया प्रस्ताव रुपए 45000 करोड़ का तैयार किया गया, जबकि इसके पूर्व यह अनुमान मात्र रुपए 12000 करोड़ का था। इस पर अनिल ने सवालिया निशान लगाते हुए केग और केंद्रीय सतर्कता आयोग से जांच कराने की मांग की है।

अंबानी अनिल हो या मुकेश दोनों ही एक नम्बर के महाजालसाज और महाडकैत हैं। स्व. धीरू की इन दोनों औलादों की जालसाजियों की जांच आयकर कस्टम एंड एक्साइज जांच करें तो कदम-कदम जनता से लूट और डकैती की कहानियां सामने आएंगी। दुनिया के जाने माने डकैत जो आज से 40वर्ष पूर्व सन 1970-80 के दशक में क्या था और वर्तमान में केंद्रीय सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखकर नचा रहे हैं तो मात्र जनता से मोबाइल के रिलायंस और स्मार्टसेल फोन के सेवाओं के नाम पर हर घंटे अरबों रुपए की बेईमानी से लूट खसोट पूरे भारत में करते हैं। शेयर्स के नाम पर विभिन्न जालसाजियों में सन 1980 से लूटपाट कर रहे हैं। इसकी जांच भी सीबीआई करे तो सारी जिंदगी इन जालसाजों के साथ इनके चार्टर्ड एकाउंटेंटस इनके सहायकों और सैकड़ों पदाधिकारियों की जेलों में सड़ाई जा सकती है। अभी ताजा विवाद जो सामने है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1956 के पहले से भारत सरकार की ये कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस का देश में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज और खुदाई करना ही था। इसने राजस्थान,बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र में कई बड़े-बड़े अच्छे काम किए थे। कावेरी, गोदावरी बेसिन के खंड-6 में जो गैस अभी रिलायंस के मुकेश के हाथ में है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसके संबंध में एक ई-मेल प्रधानमंत्री भारत सरकार को 20-7-09 को भेजा गया ता उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कावेरी-गोदावरी बेसिन की गैस राष्ट्रीय सम्पत्ति है उस पर रिलायंस ने कैसे कब्जा किया। कैसे उसके हाथ आई इसकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए। बेशक ये श्री अजमेरा की मूर्खता ही थी। जबकि पूरी कांग्रेसी गिरोह की सरकार मुकेश की कठपुतली बन नाच रही है। सारे सांसदों को वो आसानी से रुपए 50-100 करोड़ देकर खरीद सकता है। तो इस बात के लिए कौन बोलेगा, पूछेगा?

समय माया पिछले कई वर्षों से अपने पत्र में यह बात बराबर प्रकाशित कर रहा है । ठीक है, कि अभी मामला उथले पर चल रहा है इसकी जड़ में जाकर देश का कोई भी समाचार पत्र जो दैनिक प्रकाशित होते हैं, सच्चाई प्रकाशित नहीं करना चाहता।

सीजे और स्टाफ की भर्ती लो.से. आयोग या व्यापमं को ही लेना चाहिए

जजों की भर्ती उच्च न्यायालय करेगा तो अपने लोगों को भर खुलकर भ्रष्टाचार होगा

भोपाल। म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह फैसला कर लिया है कि आने वाले समय में व्यवहार न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया वो सम्पन्न करेगा, इसके बारे में जनता, प्रशासन और वकीलों की जो राय सामने आई है कि पहले से ही पूरे देश की न्यायिक प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार है अब न्यायाधीश चाहते हैं कि जो परीक्षा म.प्र. लोकसेवा आयोग लेता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता बनी रहती थई और सबको समान रू से अवसर मिल जाता था, परंतु वहां बैठे न्यायाधीशों को ये हजम नहीं हो रहा था, वो चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया अपने हाथ में लेकर केवल अपने वालों की ही भर्ती कर अपने ही खानदान, मित्रों की औलादों और उनसे जुड़े लोगों को ही न्यायालयीन व्यवस्था में आने का पूरा मौका मिले, उनके लोग ही न्यायालयीन व्यवस्था में रहे ताकि उनके पुराने पापों और भ्रष्टाचार की गठरी जो वो बांद के गए हैं उसे कोई खोल न सके।

पूरे प्रदेश के न्यायालयों में लिपिकीय वर्ग की भर्ती जो भी अभी उच्च न्यायालय के पास है वह भी व्यवसायिक परीक्षा मंडल से ही की जानी चाहिए, ताकिप्रदेश की जनता की युवा पीढ़ी को समान रूप से अवसर मिल सके। अभी तक सारा कार्य उच्च न्यायालय के माध्यम से होता आ रहा है।

न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया जबसे उच्च न्यायालय को दी गई है युवा वकीलों में भारी आक्रोश है परंतु बार कौंसिल म.प्र. इन सब बातों की ओर तथ्यों को खुलकर कह नहीं पा रहा है। दूसरी ओर लंबे समय से न्यायालयों में लिपिकिय पदों, वाचकों, शीघ्र लेखकों, टायपिस्टों की भर्तीयों के मामले में भी म.प्र. सरकार को चाहिए कि वो उनकी चयनप्रक्रिया भी व्यावसायिक परीक्षामंडल के माध्यम से समान अवसर देकर करवानी चाहिए।

जब पूरे देश में न्यायालयीन भ्रष्टाचार की चारों तरफ लोकसभा और राज्यसभा में गूंजमची हो, मीडिया न्यायालयीन भ्रष्टाचार से भरे पड़े हुए हो, दूसरी तरफ ये भ्रष्ट न्यायाधीश जनता के धन से वेतन डकार कर भी न्याय को बेच रहे हों, दूसरी तरफ कानून के पालन के लिए जिम्मेदार स्वयं ही कानून की धज्जियां उधेड़ने पर तुले हों, स्वयं भ्रष्टाचारी होने के बाद भी सरकार और प्रशासन को ईमानदारी का पाठ पढ़ायें और जब सूचना के अधिकार में जानकारी देने की बात उठे तो अपने आपको सूचना अधिकार, कानून से बाहर बताते हैं, आखिर सूचना अधिकार इन पर लागू क्यों नहीं होगा और अगर ये लागू नहीं करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि ये न केवल घोर भ्रष्टाचारी वरन कानून को बपौती समझकर उसकी धज्जियां उधेड़कर न्याय के दुकानदार हैं जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय कि उसके हिसाब से मिलेगा।

पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा ही था कि 25/1/2001 में कि न्यायालय के न्याय के मंदिर नहीं वरन जुओं के अड्डे हैं जहां जो जितना बड़ा दांव खेलता है उसे उतना न्याय मिलता है। इतनी तीक्ष्ण टिप्पणी राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के बाद भी न्याय व्यवस्था सुधरने की तो दूर स्वयं ही चयनकर्ता बनकर व्यवहार न्यायाधीशों की भर्ती की चयन प्रक्रिया पर कब्जा कर और भ्रष्टाचार को स्थायित्व प्रदान करना चाहती है। उसे अगर म.प्र. लोकसेवा आयोग में कोई कमी नजरआती है, उसकी चयन प्रक्रिया में परीक्षा लेने मूल्यांकन करने, साक्षात्कार लेने में तो उस पर सुधार बदलाव के लिए सरकार को लिए सामान्य प्रशासन मंत्रालय को कहे, बेशक भ्रष्टाचार म.प्र. लोकसेवा आयोग में भी होता है। सदस्य साक्षात्कारकर्ता लोकसेवा आयोग का संगठन उसके अधिकारी भी भ्रष्टाचार करते हैं, परंतु लिखित परीक्षा के बाद इसके विपरीत उच्च न्यायालय के हाथ में चले जाने पर तो वह पूरी ही बर्बाद हो जाएगा, जहां पर फार्म भराने से भ्रष्टाचार शुरू होगा तो चयन की और नियुक्ति और पदस्थनापा तक जाएगा। अभी यदि कोई भ्रष्टाचार लोकसेवा आयोग में होता है तो पीड़ित उच्च न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकता है, यदि उच्च न्यायालय में भी वही सबकुछ हुआ तो क्या पीड़ित सर्वोच्च न्यायालय में जाने की क्षमता रखता है। फिर कितने आवेदक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

आखिर उच्च न्यायालय को व्यवहार न्यायाधीश चयन परीक्षा को अपने हाथ में लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी। सीधा सा प्रश्न है ताकि अपनी औलादों को सीधा न्यायालयों में न्यायाधीश बनाकर बैठाया जा सके, बिना किसी शोरगुल, बिना काबलियत के या न्यायालीन कारोबार भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता रहे और जनता को न्यायालयीन प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार और षड्यंत्रों की भनक तक न पड़े, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय पर भ्रष्टों का कब्जा कर करार रहे। यह दीर्घकालीन षड्यंत्र न्याय क्षेत्र में प्रतिभाओं को आने से न केवल रोकेगा, युवा कानूनविदों की मानसिकता को कुंठित करेगा, जिसे तत्काल रोका ही जाना चाहिए।

वकीलों के समूह से चर्चा पर आधारित

म.प्र. के जिला कोषालयों में चल रहा लूट का तांडव

छठे वेतन मान के निर्धारण में चल रही वसूली

कोषालयों में अधिकारियों से रुपए 2000/- कर्मचारियों से रुपए 500 से 1000 की दर से वसूली हुई

म.प्र. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को छठा वेतनमान स्वीकृत किया। उसके वेतन मान निर्धारण के लिए न तो कोई पुस्तिका जारी की गई न ही ठोस परिपत्र जारी किया जा सके हैं। इस परेशानी को दूर करने या सभी विभागों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, वेतन बनाने वाले बाबू, बड़े बाबू ही अपने तरीके से गणना करके बिलों को जिला कोषालयों में लगा रहे हैं।

प्रदेश के पूरे 48 जिलों के सभी कोषालयों में बैठे जिला कोषालय अधिकारियों से चलकर वहां बैठे हरामखोर भ्रष्ट हर बाबू और कम्प्यूटर आपरेटरों से लेकर चपरासियों तक को हर सरकारी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से हर बिल में वसूली चाहिए होती है। यदि इन हरामखोर जिला कोषालयों में जिला कोषालय अधिकारी से लेकर सहायक जिला कोषालय बड़ा बाबू, छोटा बाबू, कम्प्यूटर आपरेटर को रिश्वत नहीं मिलती तो ये श्वनों की फौज पूरे-पूरे विभाग के वेतन तक के बिल अटका देते हैं। मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता बिल, अग्रिम सबमें खुले में म.प्र. के साथ ही पूरे देश, पूरे जिला कोषालयों में लूट का ये तांडव हर शासकीय कोषालयों में चलता है। पेंशन, भविष्यनिधि भुगतान में तो ये हरामखोर सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों, अधिकारियों के 5 से 10% वसूल करने के बाद भी दौड़ा-दौड़ कर प्राण लेने से भी नहीं चूकते। अभी जबकि छठा वेतनमान स्वीकृत हुआ है शासन भुगतान करने जा रहा है ये चपरासियों के रुपए 300 से 500, बाबुओं से बड़ा बाबुओं तक रुपए 1000 से 15000 और अधिकारियों से रुपए 2000 प्रति अधिकारी नए वेतनमान के भुगतान में वसूल रहे हैं। ये कहानी और कोषालय की गिद्ध नोंच की केवल इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, शाजापुर ही नहीं वरन भोपाल, ग्वालियर आदि प्रदेश के 48 जिलों की है।

अकेले छठे वेतनमान निर्धारण और वेतन के बढ़े भुगतान में लिपिकिय वर्ग जो पूरे प्रदेश में राज्य शासन के कर्मचारियों के रूप में कार्यरत है रुपए लगभग तीन लाख सत्तर हजार है अर्थात रुपए 1000 भी माने तो रुपए 3.70 करोड़, अधिकारियों के वेतन निर्धारण में 2000 के हिसाब से लगभग 50000 अधिकारियों रुपए 10 करोड़ और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों जो पूरे प्रदेश में 70,000 है रुपए 500 रुपए 3.50 करोड़ अर्थात रुपए 50 करोड़ की रिश्वत ये हरामखोर कोषालय के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक डकार लेंगे। प्रत्येक जिले में लगभग रुपए 1 करोड़ 10 लाख तक हर कोषालय छठे वेतनमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों से डकार लेगा।

अस्तु जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो रिश्वत डकारी है तो रिश्वत हमें भी दो, यदि सरकारी कर्मचारी रिश्वत खाते हैं तो उन्हें भी वेतन भुगतान प्राप्त करने से लेकर यात्रा भत्ता, मेडिकल बिलों, सरकारी क्वाटर आवंटन व अन्य सभी कार्यों में जैसे स्थानांतरण फंसने पर जांच रुकवाने, ठंडी करवाने, पदस्थापना, पदोन्नति, पदस्थापना में अपने बड़े अफसरों से लेकर मंत्री-संत्री तक भी धन बांटना पड़ता है जो धन नहीं दे पाता, उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। यह काम बाबू, चपरासी से लेकर जिलाधीश और सचिव स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी सभी को करना पड़ता है। पद पर बैठने के बाद रायल्टी का भुगतान लोकायुक्त, ई.ओ. डब्लू को फंसने पर महीना तक बांटना पड़ता है।

जैनियों के भगवान महावीर ने इसीलिए हजारों वर्ष पहले जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था जियो और जीने दो, को अब वह खाओ और खाने दो, में बदल कर पूरी दुनिया में फैल गया है। बस अंदाज भर बदल गया है। प्रदेश के और देश के सभी जिला कोषालयों की भ्रष्टाचार की कमाई का या छोटा सा नमूना है।

भ्रष्ट ए.सी. शुक्ला झाबुआ, मेहता पुनः धार में

आदिम जाति में भ्रष्टों की अदला-बदली

तू मेरी मत कहना और ढंकना, मैं तेरी नहीं कहूंगा और ढकूंगा

धार। आदिम जाति कल्याण में बैठा सहायक आयुक्त महाभ्रष्ट डकैत शुक्ला का स्थानांतरण झाबुआ हो गया है, वहां से पुराना डकैत सहायक आयुक्त बीजी मेहता ने पुनः धार में पदभार ग्रहण कर लिया है।

आदिम जाति कल्याण में केंद्र और राज्य सरकार का शिक्षा, छात्रावासों, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास का हर वर्ष नियोजित, अनियोजित मदों में कुल मिलाकर दो से लेकर तीन अरब रुपए तक हर वर्ष आते हैं, जिसकी बंदर बांट ये हरामखोर कैसे करते हैं पूर्व में भी समयमाया वर्षों से प्रकाशित करता रहा है।

ये दोनों ही श्वान महाभ्रष्ट, लुटेरे सफेदपोश डकैत हैं। परंतु न केवल जिलाधीशों, मुख्यकार्यपालन अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों, तक को डकैती से टुकड़े डालकर बचाकर चलते हैं। अपने आपको इनकी लूट डकैती की शिकायतें अगर पंच सरपंच या अन्य प्रति निधि करते भी हैं तो इनके पाले टुकड़खोर सांसद, केंद्रीयमंत्री कांतिलाल भूरिया से लेकर विधायक जमुनादेवी विपक्षी नेता तक इनकी पैरवी करते हैं। यही कारण है कि पिछले 8-9 वर्षों से सहायक सांख्यिकीय अधिकारी बीजी मेहता सहायक आयुक्त बनकर पहले 5-6 वर्ष धार में रहकर लूटपाट करता रहा इसके बाद भारी शिकायतों पर झाबुआ भेजा गया, वहां पर भी 3-4 वर्ष पूरे कर आया, पुनः धार में पदस्थ कर दिया गया।

जब धार में एसी बीजी मेहता था तब भ्रष्ट संतोष शुक्ला एकीकृत परियोजना अधिकारी हुआ करता था जोड़तोड़ कर और पैसा खर्च कर संतोष शुक्ला खरगोन में सहायक आयुक्त बन कर काफी घोटाले और भ्रष्टाचार में शिकायत पर निलंबित कर दिया गया था वहां से पुननियुक्ति पाकर धार में आकर जम गया था, यहां पर भी इसने खुलकर भ्रष्टाचार किया। छात्रावासों के निर्माण से लेकर छात्रावासों के लिए की जाने वाली करोड़ों रुपए की खेल सामग्री से लेकर भोजन, बिस्तर पलंग, विद्यार्थियों के लिए तेल, साबुन तक में आधी खरीदी आधे झूठे व्हाउचर लगाकर पैसा डकारा गया, जाते-जाते लगभग 400 शिक्षकों की संविदा वर्ग 1,2 व 3 की भर्ती में भी करोड़ों रुपए जिसमें रुपए 25 से 50 हजार तक खुलकर लेनदेन हुआ। स्थानांतरण पर झाबुआ पदस्थ हो गया एसी मेहता की। पिछले 4 माह से भोपाल से धार, झाबुआ तक चर्चा थी कि दोनों अदला-बदली कर स्थानांतरण की औपचारिकताएं पूरी करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ।

धार में मु.का.अ.पू.रा. धूलधोये की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के रूप में कर दी गई है। वहां के अति मुख्य का. पालन अधिकारी गुप्ता जो स्वयं जिला संसाधन विभाग झाबुआ से प्रतिनियुक्ति पर आकर 5-7 वर्षों से जमा बैठा है और दोनों हाथ से धन उलीच रहा है ने 30/07/09 को हुई जिला पंचायत की सभा में यह मिनट पास किया कि किसी भी हाल में मु.का.अ. के. रूप में आने वाले इंदौर के महाभ्रष्ट पृ.रा. धूलधोये को यहां पदस्थ करने से रोका जाए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह रा.प्र. से के अधिकारी को म.प्र. शासन ने वहां नियुक्ति दी है? क्या अ.मु.का.अ. गुप्ता जो स्वयं म.प्र. ज.सं.वि. से प्रतिनियुक्ति पर 5-7वर्षों से जमा बैठा है, अपने से वरिष्ठ को वहां पदस्थ होने से रोक सकने की औकात रखता है, क्या जिला पंचायत की सभा में ऐसा मिनट स्वीकार किया जा सकता है, वर्तमान में पदस्थ मु.का.अ.रा. श्रीवास्तव जो सचिव जि.पं. धार भी है ऐसा मिनिट स्वीकार करने में सक्षम है जिसे शासन ने पदस्थ किया और करने व हटाने का अधिकार रखता है। बेशक धार आदिवासी जिले के हर विभाग और खासतौर पर जिला पंचायत आदिमजाति कल्याण ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, पंचायत एवं समाज कल्याण डी.आर.डी.ए. एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना जिला महिला बाल विकास आदि सभी में बैठे धूर्त बाबुओं से लेकर जिला अधिकारी तक करोड़ों रुपए के चारों तरफ भारी घोटालों और भ्रष्टाचार में आंकठ लिप्त है और वर्षों से जमे बैठे हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी की भी सच्चाई सामने आए, वरना अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी सूक्ष्मता से जांच होने पर जिंदगीभर के लिए कारावास के सुपात्र हैं। जांचे आती है दबा दी जाती है। लेनदेन कर सब चुप हो जाते हैं।

निजी क्षेत्र में...

शेष पेज 5 से जारी

मुख्यमंत्री शिवराज, ऊर्जामंत्री अनूप, मुख्य सचिव राकेश साहनी और जुड़े हुए सभी सत्ताधीश सफेदपोश डकैतों का उद्देश्य है कि इस प्रकार से परेशान करके हर 6 माह में कीमतों में वृद्धि करके घरेलू उपभोक्ता को भी रुपए 10 प्रति यूनिट की बिजली आपूर्ति की जाए, ताकि प्रति यूनिट ये धूर्त, निकम्मे रुपए 1 से 2 तक कमीशन डकार सकें। इसलिए म.प्र. वि.मं. की म.प्र. पावर जनरेशन कं. की क्षमता का दिनों दिन समाप्त करने का षड्यंत्रा रचा जा रहा है।

सीधी में रिलायंस अपना ताप विद्युत केंद्र तैयार कर रहा है। जिंदल भी मैदान में है। मालवा पूरनी खंडवा का उद्घाटन हो चुका है। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो निजी क्षेत्र में लगाए जाने की तैयारी में इंजीनियरों के नाम पर आईटीआई ट्रेंड और पाली टेक्नीकल के सुपर वाइजर, इंजीनियरों के रूप में दिखाकर उन्हें 30 से 50000/- वेतन देना दिखाया जा रहा है। ताकि आयकर कस्टम एंड एक्साइज को करोड़ों का चूना लगाने से लेकर सार्वजनिक निर्गम की कंपनियों में कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ दिखाकर चवन्नी का माल चार रुपए में दिलाकर भारी कीमतों में शेयर्स पर प्रीमियम वसूली की जा सके। बाद में सत्यम जैसी हो जाए कं. की हालत इस पर न तो ऊर्जामंत्री की नजर हौ न कलेक्टर की।

अभी भी वक्त है कि इन 5 वितरण कं. और जनरेशन कं. को पुनः विद्युत मंडल में समाहित कर पुनः मंडल को अस्तित्व में लाया जाए, पुनः 1990 के सेटअप की तरह चलाया जाए सारे काम जो मंडल कर रहा था ठेव से वापिस लिए जाकर स्थाई कर्मचारियों और इँजीनियरों, अधिकारियों से ही करवाए जाएं। ताकि प्रदेश के औद्योगिक और जनता के जीवन की स्थाई विकास का पथ प्रशस्त हो, तब ज्यादा तरीके से डकार पाएंगे मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री और सभी अधिकारी, पूंजीवादी तरीके से जनता, कर्मचारियों, अधिकारियों का तो शोषण होगा ही निजी क्षेत्र के पूंजीपति न केवल भारी फायदा कमाएंगे वरन फिर मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, मुख्य सचिव, प्रधानसचिव और सचिवों के साथ इंजीनियरों को भी इन पूंजीपतियों के सामने न केर मिमियाना पड़ेगा, वरन शक्तिहीन बन दीनहीन ही होंगे।

प्र.अ. शैलेंद्र शुक्ला, स. सुलेमान राक्षस, नोंच, मिटाने पर तुले लो.नि.च.

मुख्य अभियंता कार्यालयों को बंद करने की तैयारी

सुलेमान को क्यों नहीं हटा पा रहा शिव

भोपाल।

म.प्र. लोक निर्माण विभाग के सचिव पद पर बैठा श्वान सुलेमान प्रधान सचिव पीडी मीना के कहने और भ्रष्टाचार से धन बटौरने के लिए विद्युत यांत्रिकीय अभियंता के प्रमुख अभियंता शैलेंद्र शुक्ला को मात्र नोंचने और वसूली करने के लिए ही बनाया, जबकि उस पद पर वहां सिविल इंजीनियरों के वरिष्ठ सेलेट का बैठाया जाना चाहिए था, पर इन हरामखोरों ने उस महामक्कार जालसाज जो कि पूर्व में ही नर्मदा विकास प्राधिकरण में विद्युत यांत्रिकीय अभियंता होने के बाद भी मात्र धन के लिए वहां पुर्नवास की लगभग धरमपुरी, ठीकरी व अन्य स्थानों की लगभग40 से ज्यादा पुर्न बसाहट साइटों पर लगभग रुपए 400 करोड़ स ज्यादा के काम में इस धूर्त ने पैसा खर्च किया और महातिकड़मी ने वहां छलांग लगाकर दोनों हाथों से लगभग 1 अरब रुपए पर हाथ साफ किया। कच्ची काली मिट्टी की सड़कों से भराई, डब्ल्यू बी एम के नाम पर केवल काली मिट्टी और बोहरों पर कोपरा डालकर ठेकेदारों को पूरा भुगतान, बसाहट स्थलों पर दिसम्बर में कुओं के गड्ढे किए, पानी नहीं निकला तो टैंकरों से भरवा दिया नालियों के नाम पर काली मिट्टी में खुदाई करके छोड़ दिया जो 4000 से ज्यादा बनाए गए भवनों में 5 माह बाद ही दरारें पड़ने लगी। अधिकांश भवनों की नींव में भराई की तो दूर दो फुट काली मिट्टी ढंग से नहीं खोदी गई। इस हरामखोर ने दोनों हाथ से पैसा बटोरा, इन सब घोटालों और भ्रष्टाचार का हल्ला मचे इसके पहले ही बंदा लौटकर पुनः लोकनिर्माण विभाग में आ गया और राष्ट्रीय राजमार्ग में मुख्य अभियंता बन गया। जबकि ये हरामखोर ढंग से किसी सड़क का प्राक्कलन बनाना तो दूर मूल्यांकन भी नहीं जानता था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता का मूल्यांकन बहुत दूर की कोढ़ी था। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-बम्बई मार्ग जावरा से मक्सी बनने के बाद एक बरसात में ही उसमें गड्ढे पड़ गए। और देवास-मक्सी मार्ग पिछले अक्टूबर से अभी तक बन ही रहा है, अब जब ये प्रमुख अभियंता बन गया है खुले में 5% की मांग और भुगतान पर पूरे प्रदेश के को उनके सभी संभागों के अभियंता आबंटन जारी करता है जो भुगतान के 5% नगद देने में न नुकुर करता है उसको ये श्वान प्र.अ.आबंटन ही जारी नहीं करता, स्वाभाविक है 1% सुलेमान सचिव, 1% प्र.सी. पीडी मीना, 1% मंत्री, नारेंद्रसिंग को हिस्सा जाता है। मु.ए. सेलर को इसीलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमानुसार प्रमुख अभियंता नहीं बनाया गया, चारों तरफ मुखैरों का साम्राज्य है। पूरे लोक निर्माण विभाग में सचिव सुलेमान अपनी लूट को सीधे ही कार्य पालन अभियंता से वसूली के लिए ये हरामखोर पूरे प्रदेश के मुख्य अभियंता कार्यालय बंद करने की तैयारी में है। इस कड़ी में पहले उज्जैन और रीवा के मुख्य अभियंता कार्यालय बंद किए जाएंगे। धीरे-धीरे एक-दो करके पूरे कार्यालय बंद क दिए जाएंगे, ताकि उनका सीधा नियंत्रण कार्यपालन अभियंता से होकर इन सारे हरमखोरों को सीधी वसूली मिलती रहे।

सचिव सुलेमान को आखिर मुख्यमंत्री चौहान ने पिछले 5वर्षों से सड़क विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाए रखा है, क्योंकि उसकी लूटपाट और डकैती में शिवराज की नोट गिनने वाली मशीनों को भी काम मिलता रहता है। जबकि पूरे प्रदेश के सारे बीओटी ठेकेदार अपने प्राक्कलनों का 25% भी खर्च किए बिना कच्ची-पक्की काली मिट्टी की भराई की हुई सड़कें बनाकर वसूली और डकैती शुरू कर देते हैं। जैसा कि वर्तमान में प्रदेश की 10 से ज्यादा सड़कों पर हो रहा है। इंदौर, उज्जैन 48 किमी सड़क को ही देखें तो प्रति कि.मी. दोनों तरफ जहां सड़कही नहीं बननी है तो भी 8-10 हजार पेड़ों का सफाया कर जोधपुर की ये कंपनी वाराह कंस्ट्रक्शन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर बेच कर खा गई जब समयमाया ने छापा तो उस शूकर सुलेमान ने दुगुने पेड़ लगाने का वादा कर पल्ला झाड़ लिया। दूसरा जब पूरी सड़क ही नई बनना सिद्ध करना है तो न तो ढंग से खुदाई की गई न बोल्डर्स की भराई हुई। ढंग से ऊपर से कोपरा और मुरम की जगह काली मिट्टी भराई कर समतल कर दिया गया। दूसरा जब इंदौर से 38 किमी सड़क इंदौर संभाग की थी तो उस धूर्त आर.के. माध्य को मात्रा इसीलिए इस शूकर सचिव सुलेमान ने सौंपी ताकि उल्टा-सीधा काम करवा कर मात्र ये गिद्ध धन नोंच कर उसको अच्छी सड़क का प्रमाण पत्र जारी करते रहें।

ये हरामखोर मुख्यमंत्री शिवराज शक्ल से बड़ा भोला बनता है, जबकि आने वाले 25-30 वर्षों तक जनता को हर सड़क पर गाड़ी चलाने पर पैसा वसूल करने के लिए प्रदेश की अधिकतर सड़कों पर बीओटी के हवाले कर रहे हैं। इस गिद्ध सुलेमान ने और शिवराज ने मिलकर सड़कों को जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग में आती थी छुड़ाकर पहले उन्हें राजमार्ग घोषित किया, फिर उन्हें बीओटी में सौंपा। मात्र स्वयं की भरपूर वसूली हो और ठेकेदार हर वर्ष जनता से वसूल कर 10-20% इनके चरणों में चढ़ोत्रा चढ़ाता रहे इस प्रकार अगले 25-30वर्षों तक जनता को नोंचा जा सके। यदि सारी सड़कों पर बीओटी वसूलना है तो ये सफेदपोश सत्ताधीश डकैतों का गिरोह बताए कि ये कैसी लोकतांत्रिक सरकार है? जो जनता के कल्याण की नहीं लूट तंत्र विकसित कर लूट और वसूली कर रही है। फिर सड़कें अगर बीओटी में ही देना है तो भ्रष्टाचारी बताएं कि 32% पेट्रोल-डीजल पर टेक्स क्यों वसूल रहे हैं? चौथा लोकतांत्रिक देशों में जहां सड़कों पर बीओटी का विचार लेरक आये हैं वहां पर इन भ्रष्टाचार से अंधों ने यह नहीं देखा कि एक सरकारी सड़क वहां पर मोटर कारों दौड़ाने के लिए मुफ्त भी रखी गई है। पर जहां जनतंत्र द्वारा चुनी सरकारें और प्रशासन चलने वाले सभी सत्ताधीश डकैतों की फौज हो जनता की कौन सुनेगा?

अगर सुलेमान श्वान का बस चले तो और ज्यादा समय लोक निर्माण विभाग में रहा तो न केवल मुख्य अभियंता कार्यालय अधीण यंत्रियों के वृत्त कार्यालयों तक सबको बंद करवा देगा और ऐसे डिग्रीधारी इंजीनियरों की ठेके पर नियुक्ति कर देगा जो निजी इंजीनियरिंग कालेजों के निकले हुए होंगे जिन्हें कुछ भी आता-जाता नहीं होगा, ताकि वो इसकी कठपुतली बन नाचते रह कर सारा लोक निर्माण का बजट हड़प सकें।

सांस्कृतिक सचिव, ज.स. आयुक्त मनोज श्रीवास्तव को गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस है

१५ अगस्त-जश्ने जम्हूरियत या आजादी

भोपाल।

जहां समूचा देश राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने में मग्न था वहीं अकेले म.प्र. में संस्कृति संचानालय के माध्यम से गणतंत्र पर्व मनाया गया है। यह एकदम सत्य है न कि किसी विदूषक की टिप्पणी है। यह जानकारी भरा संदेश कोई भी आम नागरिक म.प्र. की राजधानी में स्थित स्वराज भवन के द्वार पर रविन्द्र भवन के प्रांगण में तथा मुख्यमंत्री निवास के नजदीक पॉलीटेक्निक चौराहे पर संचानालय संस्कृति विभाग म.प्र. शासन के सौजन्य से लगे विशालकाय होर्डिंग तोयही बयां कर रहे हैं। ज्ञात हो कि संस्कृति सचिव के पद पर स्वयंभू विख्यात, विद्वान श्री मनोज श्रीवास्तव पदस्थ है इसके अतिरिक्त ये शासन के जनसम्पर्क विभाग के सचिव सह आयुक्त म.प्र. माध्यम के प्रबंध संचालक भारत भवन के न्यासी सहित तकरीबन शासन के आधा दर्जन पदों पर विराजमान है जो कि विद्धता के नाम पर तथा सरकार की नीतियों के प्रचार तथा प्रदेश की सत्कार सेवा के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की नाक के बाल हैं। इनके बारे में अधीनस्थ कार्यालयों में आगंतुकों से उनकी गुणगान की महिमा का बखान साक्षात सुना और देखा जा सकता है। वहीं शहर में आमचर्चा है कि इन्होंने वंदे मातरम गायन के समतुल्य संकलनों के माध्यम से तथा अपनी निजी प्रकाशित कुछ पुस्तकों के द्वारा जनता को प्रस्तुत किया है। अब प्रश्न उठता है कि शहर के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा मुख्यमंत्री सहित जनसम्पर्क विभाग, संस्कृति विभाग म.प्र. शासन के विद्वान विप्र परिवार से सम्बद्ध रखने वाले विधि का वैधानिक व विधिक ज्ञानार्जित विद्वान विभागीय मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा की फोटो सहित लगे होर्डिंग बोर्ड यह दर्शाते हैं कि म.प्र. में यों तो आजादी अथवा जश्ने आजादी की जगह जश्ने जम्हूरियत मनाया जा रहा है। अर्थात स्वतंत्रता पर्व नहीं गणतंत्रा पर्व मनाया जा रहा है। यह करिश्मा भी वह विभाग कर रहा है जो संस्कृति के प्रचार विस्तार के लिए जनजागरण अभियान चलाने तथा संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी/

जवाबदारी संभाले हुए हैं। इन विभिन्न विशालकाय होर्डिंगों को देखकर आम जनचर्चा कि यह संस्कृति सचिव एवं संचालक श्री मनोज श्रीवास्तव जनता में गलत व दुष्प्रचार कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वहीं यह भी चर्चा है कि इनके द्वारा भविष्य में देशद्रोही असामाजिक तत्वों के सहयोग करने की नीयत से कोई देशद्रोही गतिविधि को अंजाम देने का इरादा तो नहीं पाले हुए है। यह दुष्प्रचारित कार्य श्री मनोज श्रीवास्तव सचिव की कुर्सी पर बैठकर साल दर सार निरंतर करते चले जा रहे हैं। अब प्रदेशभर के बुद्धिजीवियों में यह भी संदेह पैदा हो गया है कि इनके द्वारा लिखित पुस्तकें तथा संकलन कहीं चोरी के तो नहीं हौ। उनकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि जहां ये बैठे हैं वह पर अमूल्य साहित्यों का भरापूरा भंडार है। वहां उनके विरुद्ध पूछ परख करने वाला कोई नहीं। इन सभी शंकाओं, दुष्प्रचारित कार्यों का खुलासा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान व राष्ट्रीयपर्व को मनाने से पहले चाहिए कि वह कौन सा पर्व मना रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्राता दिवस अथवा गणतंत्र पर्व। और संतुष्ट करें देश की अवाम को।

जब यह समाचार दिसमें होडिंग का फोटो जिसमें जश्ने जम्हूरियत लिखा गया था के संबंध में 14.08.09 को रात्रि 11.17 पर मुख्यमंत्री निवास पर फोन पर पूछा गया कि प्रेदश क्या मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस तो मु.मं. कार्यालय में जो भी कर्मचारी था उसने उल्टे ही पूछा कि क्या आपको नहीं मालूम, तो उनसे कहा गया कि आपको होर्डिंग्स तो जश्ने जम्हूरियत अर्थात गणतंत्र समारोह आयोजित कर रहे हैं। 15 अगस्त पर वो फिर पूचा गया कि ऐसा कहां लिखा गया है तो बताया कि स्वराज्य न्यूज. काम पर आपके संस्कृति सचिव द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स पर बताया जा रहा है, तो जवाब मिला कि ठीक है मैं मालूम करता हूं।

ये वही इंदौर के पूर्व कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव है जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्गीदानव की हवाई अड्डे पर अटैची उठाकर आगे-पीछे होते रहते थे। .ये भी महाभ्रष्ट आखिर कलेक्टर होने के बाद भी मुख्यमंत्री की अटैची उठाते थे अब प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त संस्कृति सचिव सभी कुछ है, इसलिए ये आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रति सामदाम दंड भेद से समर्पित होकर आम आजादी पर गणतंत्रता दिवस मनाएं और गणतंत्रता पर आजादी, दिखाने के लिए ये मुख्यमंत्री के प्यादे हैं पर वास्तविकता में ऐसे धूर्त आई.ए.एस. अधिकारियों के मुख्यमंत्री स्वयं प्यादा होता है, जैसा ये कहेंगे गद्दी पर बैठा प्यादा स्वीकारेगा आंख बंदकर करना चाहिए।

बजाज सीटी १०० सफल थी जबकि बजाज प्लेटिना औसतहीन, दहशतगर्दी

रुकमणी मोटर्स ने कहा, कम औसत दे रही है तो ४० के ५० बीच चलाएं

बजाज आटो लि. ने जितनी इस देश की बर्बादी की शायद पूरे देश में इतना पर्यावरण बिगाड़ने की उपभोक्ता की जेबों और जीवन की सेहत बिगाड़ने में इनका सानी नहीं रहा।

सन 1960 से स्कूटरों का निर्माण किया 30 से 45 का औसत ही दे रही है। वह भी जब उपभोक्ता तरीके से रखरखाव करे अर्थात् 48 वर्ष में बजाज आटो का प्र. संचालक राहुल बजाज सन 1998 में जबलपुर के शोरूम के उद्घाटन के वक्त जब यही बात पूछी गई कि आपने 38वर्ष में अपने चेतक सुपर, प्रिया में औसत क्यों नहीं सुधार पाए तो जवाब में इस उद्योगपति राहुल बजाज का कहना था कि पेट्रोल में 100 ग्राम मिट्टी का तेल मिला दीजिए। उसकी इस हरकत ने वहां बैठे पत्रकारों को हैरत में डाल दिया कि प्रश्न क्या था और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक क्या जवाब दे गया।

वर्तमान में बजाज आटो लि. की आने वाली सारी बाइक्स में जो औसत यह कंपनी बताती है वास्तविकता में सड़क पर वह औसत नहीं मिलता, यदि ये औसत का 25% कम कर भी दें तो पाठकों को यह बता देना जरूरी है कि इन जालसाज हरामखोरों ने 25% मीटर तेज कर रखे हैं। इंदौर से धार 60कि. आनाजाना 120 +10%= 132 किमी मान लें तो 50 कि.मी. तीन ली पेट्रोल समाप्त, मीटर बताता है 200 कि.मी. इंदौर से देवास 35 कि.मी. आना जाना 70 कि.मी.+ 10%= 77 कि.मी. बताएगा 100 किमी 2 ली. पेट्रोल पूरा साफ, इंदौर से उज्जैन 50 कि. गुणा-2= 100 कि. +10% कि.मी. और 10% भी जोड़ दें अर्थात 120 कि.मी. बताएगा। 155 किमी तीन ली. पेट्रोल समाप्त।

यह बात 25 जून 09 को रुकमनी बजाज से प्लेटिना साधारण खरीदी थी से कही गई तो पहले तो वहां के मिस्त्रीयों तक्नीशियनों ने नहीं-नहीं की बाद में जब बहस होने लगी तो कहने लगे आप इसे 40

60कि.मी. की गति से चलाइये तो औसत 70 का मिल जाएगा तो पूछा गया कि जो मीटर गाड़ी में लगा है उससे बोले और क्या तो उनसे कहा गया कि यह 25% तेज चलता है, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब बोला गया कि बिल्कुल हो सकता नहीं ऐसा ही है। पाठकों को बता दें कि कं. 107 कि.मी. लिखती है जबकि जो गाड़ी श्री अजमेरा ने खरीदी जिसका पं.क्र. एम.पी.-09 एम.यू. 7630 है। 40 कि.मी. से ज्यादा का औसत नहीं दे रही है।

दूसरा इस गाड़ी को 70 किमी की प्रति घंटे की गति या उससे तेज चलाने पर गाडी के हैंडल में कंपन होने लगता है। तीसरा इन हरामखोर निर्माताओं ने हेड लाईट के ऊपर जो बिंडशील लगाई वह भी बजने लगती है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस गाड़ी को खरीदने का मूल कारण था कि बजाज की पूर्व की सीटी 100 गाड़ी का औसत 50-55 ही था, परंतु 90-100 कि.मी. की गति से चलाने पर न तो कंपन पैदा होते थे वो ताड़ी वाले पहियों की सुरक्षित और न्यूनतम खर्च की दूसरी गाड़ियों की अपेक्षा रखरखाव की गाड़ी थी यह सोचकर कि वह अच्छी गाड़ी थी यह भी अच्छी होगी, चूंकि वह 4 लाख किमी से ज्यादा चल चुकी थी बेचना आवश्यक होगया था। आखिर बजाज ने अपनी ताड़ी के पहिये वाली गाड़ियां बनाना क्यों बंद की, ताकि गड्ढों में कुदाने या चली जाने पर पहिये की डिस्क थोड़ी सी भी चटके तो उपभोक्ता को पूरा हजार डेढ हजार का पहिये की पूरी डिस्क को ही बदलवाना पड़े और इन हरामखोरों डीलरों, डिस्टीब्यूटरों के साथ कंपनी की भी कमाई हो सके और कंपनी को कमाई होती रहे।

डीलर रुक्मणि ने पहली मुफ्त सर्विसिंग की परंतु ये फौज भी उसका औसत नहीं सुधार पाई है। ये बजाज की सीटी100 से तो कई अर्थों में बकवास है। पाठक खरीदने से पहले सोचें या अन्य विकल्पों पर ध्यान दें।

रक्त पिपासु दानव है मनमोहन

शेष पेज 8 से जारी

अपनी कमाई और कमीशन खोरी के लिए दानवराज प्र.म. मनमोहन और कृषि मंत्री शरद पंवार जो कुत्सित चाले चल रहे हैं कि पहले अच्छी गुणवत्ता दालों, गेहूं, चावल, शक्कर खाद्य तेल, सूखे मेरे, मसालों, गुड़ आदि में दैनांदिनी उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात की बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पूंजीपतियों को मोटा कमीशन डकार कर पूरी छूट दे दो, जब देशी बाजारों में सबकी कीमतें आसमान छूने लगे, पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. और बड़े निर्यातकों के सारे गोडाउन खाली हो जाए जनता भूखी मरने लगे त्राही-त्राही मचने लगे तो फिर प्रेस कांफ्रेस बुलाओ, टीवी पत्रकारों को बुलाओ और बड़े-बड़े गिफ्ट बांटकर अपनी तारीफें छपवाओं और घड़ियाली आंसू बहाते हुए सहनुभूति जताते हुए अपने मक्कारीपूर्ण अदाओं से दर्द बहाते हुए घोषणा करो कि हमने निर्यात बंद कर दिया है। दूसरी ओर फिर जनता की परेशानियों और महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की कमी का गुणगान करते हुए दूसरी घोषणा करते हैं कि हमने जनता की जरूररतों को ध्यान में रखकर 5 लाख टन शक्कर (जो कचरा था और विदेशी गोदामों सड़ रही थी) उस पर सरकारी अनुदान देकर राशन दुकानों से बंटवाने की व्यवस्था सरकार के ये दानव 200% कमीशन डकार कर राशन की दुकानों से बिकवाएंगें। यही हाल दालों, चावल, गेहूं, मसालों, खाद्य तेलों में भी ये दानव अपने कमीशन के लिए अपने भाई-भतीजों की फर्मो और कंपनियों के माध्यम से करवा कर एक ही झटके में उन्हें अरबपति, खरबपति बनवा देंगे।

पिछले 5 वर्षों से जैसा कि गेहूं, चावल, दालों, मसालों, सूखे मेवों, तिलहनों में होता आ रहा है अच्छा बासमती चावल यहां से रुपेप 35 रुपए 40 रुपए प्रति कि. सरकारी खरीद हुई अच्छी गुणवत्ता का गेहूं रुपए 9 से 11 प्रति कि खरीदा गया और से रुपए 20-25 प्र. कि. के भाव में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच कर मोटा कमीशन डकारा गाय, दूसरी ओर जब गेहूं की कमी का रोना बताकर सड़ा लाल आस्ट्रेलियन गेहूं जो 50पै. कि. में खरीदा गया था कि खरीद रुपए 14प्र. कि. दिखाकर रुपए 13/50 डकारे गए। दूसरी और उस गेहूं का राशन दुकानों से बांटने के लिए रुपे 12प्र कि. का अनुदान दिया गाय, जबकि वह अनुदान मंत्री पुत्रों, उनके दोस्तों की बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ही डकारा। बेशक उसका हिस्सा प्रधानमंत्री, कृषिमंत्री, वाणिज्यमंत्री जसे कांग्रेसी गिरोह के दानवों ने भी डकारा।

अब कृषि मंत्री शरद पवार दानव चिल्ला रहा है कि वायदा व्यापार हे मुख्य कारण महंगाई का तो है जनता के रक्त पिपासु दानवों उस वायदा व्यापार को चालू भी तो तुमने अपने कमीशन को नोंचने और जनता को भूखा मारने के लिए ही किया है। समयमाया समाचार पत्र पिछले पांच वर्षों से बराबर प्रकाशित कर रहा है कि ये कांग्रेसी गिरोह के धूर्त, मक्कार, दानव जनता को नोंचने और बाजार में महंगाई बढ़ाकर लूटने के लिए कैसे-कैसे षड्यंत्र रचकर गरीबों के मुंह से दालरोटी छीनकर अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं।

कांग्रेसी गिरोह का ये ऐतिहासिक आधारभूत सिद्धांत है, यदि सत्ता में बैठकर जनता की नहीं की नुंचाई जनता को उससे नहीं आई रुलाई तो समझो सत्ताधीशों की शामत आई, इसलिए आवश्यक है जहां से मिलें जैसे मिले करो खूब कमाई, जिससे जितना जनता चिल्लाएगी उसे रुलाई आएगी भूख सताएगी, उसकी औलादें भूख से तड़प मर जाएंगी। तब हमें घड़ियाली आंसू बहाते हुए सहानुभूति बरसाते हुए जनता से रूबरू होते हुए मीडिया में सौगातों की बारिस करेत हुए शक्ल दिखाने की बारी आएगी। तब हमारी औकात जनता को समझ आएगी। समयमाया ने यह तथ्य वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, यदि सच्चे दिल से ये धूर्त दानव मनमोहन पंवार, कमलनाथ, चाहे तो कुछ घंटों में ही महंगाई का पारा ठंडा हो सकात है, बशर्ते आयात-निर्यात की नौटंकी और वायदा बाजार तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। जो ये इनके सत्ता में रहने तक कभी नहीं कर सकते। झूठी सफाई, झूठे आंकडे, घड़ियाली आंसू, जालसाजी राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के हितों को पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. को बेचने गिरवी करने से लेकर ये गंदी और नीच मानसिकता को गिद्ध गिरोह अमेरिका ब्रिटेन को गिरवी करने से लेकर पाकिस्तान, चीन, नेपाल और श्रीलंकाई शत्रुओं को भी गिरवी करने से नहीं चूकता।

देवास स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का तांडव

इंदौर कांड की पुनरावृत्ति देवास में भी

देवास स्वास्थ्य विभाग ने पंडित के समय में खूब जीपीएफ निकाला

वर्तमान में इंदौर में पदस्थ महाभ्रष्ट मीठा बोल, महामक्कार, जिसकी बत्तमीजियां, भ्रष्टाचार आए दिन इंदौर के समाचार पत्रों में छपती है। इसके बाद भी म.प्र. सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा मोटी चमड़ी के इन श्वानों की औकात नहीं कि इस इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद पंडित को यहां सेहटाकर बालाघाट, रीवा, मुरैना भेज सकें, क्योंकि वह हरामखोर भ्रष्टाचार से करोड़ों डकारता है तो कुछ लाखों के टुकड़े ऊपर बैठे प्रधान सचिव देवराज बिरदी, संचालक अशोक शर्मा जैसे भ्रष्टों का येनकेन प्रकारेण सब धन के भूखे हैं, उन्हें टुकड़े मिल जाते हैं, इसलिए वो सब भी ऐसे ही भ्रष्टों को पालते पोसते रहते हैं।

डॉ. शरद पंडित ने जो घोटाले इंदौर में किए थे उसमें 99% दबा दिए गए थे

पर एक जो पकड़ा गया था उसमें था कर्मचारियों का भविष्य निधि घोटाला था, जिसमें डॉ. शरद पंडित को चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया था। जिसमें डॉ. पंडित को जमानत करवाई थी, जिसमें भी लाखों रुपए खर्च करके अपने आपको बचाया था। यहां से इन आरोपों के चलते संयुक्त संचालक से पदोन्नत कर पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाकर देवास में पदस्थ कर दिया गया था। देवास में जाकर इसने जीपीएफ घोटाले की पुनरावृत्ति की और कम से कम 25-30 कर्मचारियों का जीपीएफ निकाला गया, वहां की रोकड़ का सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कहां वर्ष में एक दो कर्मचारी जीपीएफ निकालते हैं, अचानक इसके वहां पदस्थ होते ही अनेकों कर्मचारियों ने जीपीएफ की किश्तें निकाल लीं। घोटाले तो और भी हैं करोड़ों रुपए दवाई खरीदी में डकारा गया। यहां जो जीपीएफ की किश्तें निकालने का प्रमाण जो दस्तावेज सूचना के अधिकार के अंतर्गत दो वर्ष बाद आए, उनका विश्लेषण इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि देवास स्वास्थ्य विभाग के सभी तकनीकी लिपिकीय और चिकित्सालयों का स्टॉक सन 2005 से अपने जीपीएफ की जमा पर्चियों की खाते से जांच कर ले नहीं तो सीधे अपने उच्च अधिकारियों, जिसमें बीएमओ, सीएमओ, देवास, लेखापाल के विरुद्ध सीधा थाने में एफआईआर लिखाए और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो के साथ लोकायुक्त में भी प्रकरण दर्ज करवआएं, सन 2005, 2006 और 2007 में दीपीएफ का किसको कितना भुगतान किस चेक नं. से किया गया जांचें, अन्यथा कर्मचारी भी सूचना के अधिकार में अपने आवेदन स्वीकृति की नोटशीट स्वीकृति का दिनांक और चेक जारी करने वाले व हस्ताक्षर जारी करने वाले लेखापाल बीएमओ, सीएमओ से प्रतियां प्राप्त कर पुष्टि करें।

सीएमओ देवास जीपीएफ २००७

क्र.	दिनांक	विवरण	दिनांक	रुपए	कुल
16.	19.01.07	बिल नं. 950 बीएमओ सोनकच्छ को जीपीआर पार्ट फायनल का चेक क्र. 133548 का दिया	2.01.07	40000	40000
60.	26.07.07	बिल नं. 352 जीपीएफ पार्ट फायनल डॉ. आर.सी. मुंदडा, पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच देवास में 325000 जमा किया	11.7.05	285000	285000
44.	28.11.06	निम्न कर्मचारियों के जीपीएफ एवं अग्रिम पंजाब नेशनल बैंक देवास में जमा किए विजया तगारे प्रकाश साठे ईस्माइल अली मनोरमा सांगते		 50000/- 50000/- 50000/- 15000/-	165000
46.	28.11.06	बिल नं. 803, 304, 806 बीएमओ बरोठा के निम्न जीपीएफ के बिलों के चैक दिए गए चैक 029357 029358 029354	17.11.06 25.11.06	125000 70000/- 30000/- 25000/-	
19.	17.10.06	बिल न. 6/4 जीपीएफ फाय पैमेन्ट कमलाकर जुठे का पंजाब बैंक देवास में जमा किए बिल 671	22.09.06 147062 12.10.06	 147062	
20.	17.10.06	जीपीएफ पंजाब बैंक देवास में जमा किया आर.के. डी. वर्मा बिल नं. 671	 12.10.06	10000/-	10000
24.	20.07.06	जीपीएफ पेमेन्ट मांगीलाल सिया को भुगतान किया चैक क्र. 653135 दि. 9.7.06 को बीएमओ सोनकच्छ को दिया बिल नं .342	 21.06.06	210164	210164
25.	20.07.06	जीपीएफ पांट काय डीपी व्यास का चेक क्र. 653127 दिनांक 19.7.06 का बीएमओ सतवास को दिया बिल नं. 406	 10.07.06	3000	30000
25बी.	20.07.06	जीपीएफ अग्रिम चैक क्रं. 65324 दि. 19.07.06 बीएमओ ठोकर्स को दिया। सी.पी. साठे 5 बिल नं. 37 जीपीआर काटा, पेमेन्ट का चेक 653134 दिनांक 19.07.06 को बीएमओ बागली को दिया बिल 412 जीपीएफ	 26.6.06 13.07.06 2006	15000 36822 21822 टोटल	 814048
61	26.7.05	जीपीएफ पार्ट फाय. मनोज बेंजामिन का पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच देवास में जमा किया		35000	35000
62.	26.7.05	निम्न बीएमओ को जीपीएफ. व अन्य डी.ओ. से भुगतान किया बीएमओ बरोठा डीडी नं. 697308 खातेगांव 697309-/- सतवास 697310/- सोनकच्छ 697311-/-	 25.7.05	15000 15000 29643 30000	 89643
25.	28.11.05	जीपीएफ. बिल नं. 723 आरती विश्वास का पंजाब नेशनल बैंक देवास में जमा किया चैक 579400 दिनांक 25..11.05	21.11.05	15000	15000 139643

साप्ताहिक
समय माया

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे षड्यंत्र वर्षों से

भारतीय युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी

यौनशिक्षा, समलैंगिकता, 12वीं तक परीक्षा नहीं, सब प्रत्यक्ष प्रभाव है यह सब यूरोपीय षड्यंत्र है, ताकि विश्व में बढ़ता भारतीय प्रतिभाओं का प्रभाव और कब्जा न हो जाए, आने वाली पीढ़ी स्कूलों में ही बर्बाद हो जाए, इस षड्यंत्र में कांग्रेसी भी शामिल हैं

राष्ट्र में कांग्रेसी सत्ता को जनता के कल्याण से नहीं वरन कल्याण के नाम जनता की चहुंदिशि बर्बादी और उससे उसकी कमाई से होता है। उसे इस काम में विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर राष्ट्र की ओर वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने से भी गुरेज नहीं है, वह पीढ़ी जिसके लिए उसके माता-पिता अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर पढ़ाते लिखाते हैं। फिर वह विदेशों में काम करके भारत सरकार को अपनी कमाई से धन कमा कर देती है। पिछले 20 वर्षों से कमा कर भेज रही है।

पूरे यूरोप में भारतीय प्रतिभाओं का जो डंका बज रहा है, पिछले 20-30वर्षों से उससे यूरोपीय देशों में चारों तरफ खलबली मची हुई है। पिछले 10 वर्षों से ही देखें तो पहले बिल क्लिंटन बाद में बुश और अब बराक हुसैन ओबामा भी लगातार जिन भारतीयों के दम पर अमेरिकी सत्ता और उसकी अर्थव्यवस्था चला रहे थे और चला रहे हैं लगातार भारतीय प्रतिभाओं से अमरिकी जनता और उसकी पीढ़ीयों को चेतारहे हैं कि भारतीयों से सावधान रहे उन्होंने सारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया है, जागो अमेरिकी युवा खूब पढ़ाई करो वरना भारतीय प्रतिभाएंहर जगह कब्जा कर लेंगी।

इसके दूसरी तरफ वही अमेरिकी उसका माइक्रोसाफ्ट कं. का मालिक बिलगेट यहां एड्स के नाम पर अपने साफ्टवेयर की बिक्री से अरबों कमाया है उसका 1% कम भारतीय मुखैरों, अर्जुनसिंग, कपिल सिब्बल जैसों को दान कर स्कूलों में यौन शिक्षा बांटने की पैरवी करवाता है, ताकि युवा पीढ़ी स्कूलों और कालेज में ही यौनाचार के चक्कर में पड़कर अपना तन और मन दोनों बर्बाद कर भारत में ही छोटी-मोटी नौकरी धंधा कर बैठा रह सके यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व अन्य देशों की तरफ न जा सके। कभी अर्जुनसिंग, कभी कपिल सिब्बल यही कारण है कि 5वीं, 8वीं, 10वीं की परीक्षा को समाप्त करते हैं, ताकि 12वीं तक तो आसानी से पहुंच जाए, परंतु उसे नाम भी लिखना न आता हो, फिर कालेजों में भी जाएंगे तो भी वह वहीं सड़कर रह जाएं, बेशक यह मुस्लिम वोट कबाड़ने की चाल का हिस्सा भी है। पूरी दुनिया में छाए भारतीयों के बारे में आसानी से बदनाम कर उन्हें यूरोपीय देशों में गंवारों के नाम से पुकार कर बदनाम किया जा सके और वहां पर डिग्रीधारी भी मजदूरों और श्रमिकों की तरह उपयोग किया जा सके, गुलामों की तरह।

बची खुसी कसर जो रही थी, उसे दिल्ली उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी कर दी। स्कूलों में कंडोम बेचने और एड्स के बचाव के नाम पर स्कूलों में यौन शिक्षा के नाम पर पहले उनको यौनाचार के लिए उत्प्रेरित करो, यौन शोषण करके नपुसंक बना दो, 12वीं तक परीक्षाओं को समाप्त करके पढ़ने और परीक्षा के भय से मुक्ति देकर पढ़े-लिखे गंवार जब युवा अवस्था में पहुंचे तो समलैंगिक व्यवसाय में झोंककर कमाई की व्यव्सथा करवा दो अर्थात सारा यौवन इहीं कुकर्मों में भारत में ही सड़ जाएगा। तो विदेशों तक ये भारतीय पहुंचकर कब्जा नहीं कर सकेंगे और पहुंच भी गए तो इन कुकर्मों के कारण बदनाम होंगे तो गुलामों को जेल में डाल देंगे।

दूसरा बड़ी नौकरियों, प्रबंधन, वैज्ञानिकों, से लेकर सीनेदारों के पद पर बढ़ते भारतीयों के कदमों को रोकने, अमेरिकी और यूरोपीय देशों में उनकी आबादी का हिस्सा बनने से लेकर उनके अर्थतंत्र के प्रमुख अंग बन जाने से जो खतरा पैदा हो गया है। उसको रोकने के लिए युवी पीढी को बर्बादी का हर षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें यौन शिक्षा, कंडोम की मुफ्त उपलब्धता, इंटरनेट पर स्वच्छंद यौनाचार की उपलब्धता, परिवारवाद के लिए खात्में के लिए फेसबुक,यौनाचार संबंधित ब्लाग्स जानी मानीसाइटों पर उपलब्ध है। ये आगे बढ़कर समलैंगिकता को बढ़ावा, न्यायालयों से मुक्ति और छूट वैधानिक बनाना, 5वीं, 8वीं 10वीं की परीक्षाओं की समाप्ति बाद में समलैंगिकता के कालेजों में क्लब आदि सब उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी पढ़ाई पर से ध्यान न लगा कर इन कार्यों में ही उलझकर चौपट हो जाएं।

आखिर वृद्धों की बढ़ती आबादी भी इस सामाजिक प्रदूषण को रोकने का कार्य भी नहीं कर पा रही है, सामाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन सारे हरामखोर क्या केवल दुकानदारी चलाने के लिए और धन बटोरने के लिए ही बैठे हैं। मेरे प्रिय पाठक, अपने देश की वर्तमान और आने वाली युवी पीढ़ी को बर्बाद करने के अंतरर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सत्त में बैठे धूर्तों को षड्यंत्रों को आसानी से समझ चुके होंगे।

बेशक राष्ट्र में वैश्यावृत्ति समलैंगिकता को अंतरराष्ट्रीय यौनाचार से कमाई करने वाले इंटरनेट के माध्यम से चलने और चलाए जाने वाले गिरोहों के इशारे पर न केवल भारत सरकार वरन न्यायाधीश भी इसीलिए वैधानिक बनाने पर तुले हैं। ताकि स्वच्छंद यौनाचार से इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए प्रतिवर्ष की कमाई की जा सके। उसका मोटा कमीशन केंद्रीय सत्ता में बैठे ये धूर्तहरामखोर जालसाज मंत्री जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। दोनों हाथ से डकार कर विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हैं।

न्यायालयीन व्यव्सथा में कदम-कदम भारी भ्रष्टाचार होने के बाद भी जनता को न्याय व्यवस्था पर विश्वास जमा रहता है। परंतु जबसे दिल्ली उच्च न्यायालय का समलैंगिकता के पक्ष में फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध लगी अपील ठुकराई गई है। जनता का बुद्धिजीवी वर्ग भारी आक्रोशित है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के भ्रष्टाचार और जनता के भविष्य के हितों पर कुठाराघात करने से।

पहले अच्छा माल निर्यात फिर सड़ा आयात, दोनों में कमीशन वसूली

रक्त पिपासु दानव हैं मनमोहन, शरद पवार

मुद्रास्फीति ऋणात्मक-दोनों स्वीकार रहे हैं मंहगाई बढ़ रही

वर्तमान में भारतीय मीडिया दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सरकारी आंकडों के अनुसार दिखा रहे मुद्रा स्फीति पिछले 30वर्षों में ऋणात्मक 1.38% हो गई है। पिछले छह महीने से कांग्रेसी सरकार का डाटा और सांख्यिकी विभाग कितने विश्वसनीय समंक सरकार और मीडिया को जनता को भ्रमित करने और अपनी वाहवाही छपवाने के लिए जारी कर रहा है। इसका अंदाज एक आम आदमी तो लगा पा रहा है, परंतु मीडिया के देख के बड़े-बड़े सरकारी भांडों जिसमें भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, जागरण व राष्ट्र के लाखों समाचार प्रकाशक पत्रों को समझ नहीं आ रहा है।

दूसरी ओर सत्ता में विराजमान कांग्रेसी प्रधानमंत्री दावन राज सिंग और पंवार मीडिया में स्वीकार कर रहे हैं कि हां न केवल महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी की दहशत भी दे रहे हैं। इसके विपरीत सरकारी तंत्र मुद्रा स्फीति ऋणात्मक दिखाने अपनी कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन बंद नहीं कर रहा।

समयमाया ने अपने कांग्रेस की सत्ता संभालते ही जैसा लिखा था कि कांग्रेस की सत्ता महंगाई आतंकवाद राष्ट्र बेचने, जातिवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों की रखैल बन कर नाचने का पर्याय है। वह कदम-कदम पर स्वयं सिद्ध हो रहा है। महंगाई दिनों दिन क्यों बढ़ रही है इसके बारे में समयमाया ने जो कारण बताए थे वो स्वयं अपनी सत्यता को पारिभाषित कर रहे हैं। **शेष पेज 7 पर**

विश्व का सबसे बड़ा दैत्य बिल गेट्स माइस्कोसाफ्ट कं.

२०० करोड़ से ज्यादा कम्प्यूटर चालकों को करता है परेशान

कम्प्यूटर बेचें, साफ्टवेयर बेचें, सबमें हजारों गुना लूटने के बाद भी वायरस भेज कर जाम करना, नोंचने के लिए अरबों को परेशान करता है इसे चीन, उत्तरी कोरिया, ईरान, रूस अजन्म कारावास दे सकते हैं

दुनिया में माइक्रोसाफ्ट का बिलगेट जैसा बड़ा दैत्य कोई नहीं। यह नीच डकैत शीघ्र खराब हो जाने वाली ऐसी कम्प्यूटर सामग्री जिसमें हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड से लेकर सैकड़ों सामग्रियों, रेम व अन्य कलपुर्जे जिन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, को सैकड़ों गुना लाभ पर बेचने के बाद भी फिर साफ्टवेयर प्रोग्राम्स जिससे कम्प्यूटर योग्य बनता है। इन साफ्टवेयर की सीडी आदि पर भी करोड़ों रुपए लाभ कमाता है। कोई भी साफ्ट वेयर का जीवन दो वर्ष से ज्यादा नहीं होता, वह अपने आप काम करना बंद कर देता है। इस प्रकार किसी भी प्रयोग साफ्टवेयर की एक सीडी से ही ये अरबों सीडी बनाकर अरबों रुपए कम्प्यूटर का उपयोग करने वालों से नोंच मारता है।

विश्वभर में कम्प्यूटर के आपरेटिंग सिस्टम विन्डोज पर इस नीच श्वान का कब्जा है, जिससे खरबों डालर यह कमाता है इसके बाद भी इस राक्षस का कभी पेट नहीं भरता। वर्तमान में चूंकि हार्डडिस्क के आपरेटिंग सिस्टम के विन्डोज एक्स.पी. विन्डोज विस्तार पर इसका कब्जा है आन लाईन होते ही सारी जानकारी इसके अमेरिका स्थित कार्यालय में दुनियाभर से पहुंचती रहती है। जो इसके द्वारा बेचेगए प्रोग्राम साफ्टवेयर और उसके प्रोग्राम की प्रति के नम्बरों से मिलान होते ही वहां शूकरों की फौज संबंधित कम्प्यूटरों को रोकने के लिए वार्निंग, ई-मेल भेजने, मूल साफ्टवेयर की कापी आनलाइन खरीदने के लिए विवस करती है न खरीदने पर कम्प्यूटर में वायरस भेजकर जाम करना कम्प्यूटर में भारी सामग्री को साफ करना, फिर भी न मानने पर ये नीच हार्डडिस्क बैठा देने डाटा साफ कर देने से भी नहीं चूकते।

यदि आपने हजारों रुपए के इन कार्यक्रम साफ्टवेयर की मूल सीडीयां खरीद भी लीं तो भी ये कार्यक्रम 2वर्ष के बाद काम करना बंद कर देंगे। अर्थात कोई भी प्रोग्राम जो रुपए 10 हजार से लेकर लाखों रुपए की कीमत का भी हो सकता है 2वर्ष बाद आपकी निवेशित पूंजी डूब जाएगी। इस प्रकार बिल गेट माइक्रोसाफ्ट कंपनी हर दिन अरबों रुपए पूरी दुनिया से बटोरती रहती है।

इस राक्षस का अब दानी रूप भारत में 2000 करोड़ डालर एड्स के लिए पूरी दुनिया के शूकर डॉक्टरों से पूछो कि दुनिया में एड्स कौनसी बीमारी है तो सच्चे अर्थों में एड्स कोई बीमारी नहीं, वरन 10 पैसे के कंडोम को दस रुपए में बेचने का षड्यंत्री हथियार है। पाठकों को बता दें एड्स से आज तक कोई भी नहीं मरा, क्योंकि कोई बीमारी होती तो मरता न, फिर रुपए अ. डालर 2000 करोड़ क्यों दिए? ताकि इस देश के मुखैरे शासकीय पदों पर बैठे भारत सरकार के आई.ए.एस. श्वानों को टुकड़ा डालकर खरीदा जा सके और पूरे देश के केंद्र व राज्य शासित शासकीय **शेष पेज 4 पर**

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2304377 मो. 93007-55803